



RNI NO. CHHHIN/2022/83778

न्यूज़ रूटीन

मासिक, बलौदाबाजार से प्रकाशित

बढ़ते हुए कदम

वर्ष : 03

अंक : 07

मासिक, बलौदाबाजार, जुलाई 2024

E-mail: newsroutine6@gmail.com

पृष्ठ : 08

मूल्य : 15 रु.

अगर आपने दर्द में भी
मुस्कुराना सीख लिया तो
समझिए आपने जिन्दगी
जीना सीख लिया

मुख्यमंत्री साय ने 'एक पेड़ मां के नाम' महा वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ प्रदेशव्यापी अभियान के तहत 33 जिलों में होगा 4 करोड़ वृक्षों का रोपण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर के अटल नगर स्थित जैव विविधता पार्क में 'एक पेड़ मां के नाम' महावृक्षारोपण अभियान-2024 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पूर्ण विधि विधान से पूजन कर पीपल के पौधे का रोपण कर महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री द्वारा अभियान का बैनर जारी किया गया। इस अभियान के तहत वन विभाग द्वारा प्रदेशभर में 4 करोड़ वृक्ष लगाये जाएंगे। इसी के अंतर्गत में आज प्रदेश के 33 जिलों में कुल 4 लाख पेड़ लगाए गए। आज महावृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ के मौके पर जैव विविधता पार्क में मुख्यमंत्री श्री साय के साथ सभी कैबिनेट मंत्रीगणों, स्कूली बच्चों, सीआरपीएफ के जवानों, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने 20 हजार पेड़ लगाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने ओपन जिप्सी में वृक्षारोपण क्षेत्र का भ्रमण कर अभियान में हिस्सा ले रहे लोगों का उत्साह वर्धन किया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव एवं श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बबेल, श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं



बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री श्री टंक राम वर्मा, विधायक श्री इंद्र कुमार साहू एवं श्री गुरु कुशवंत साहेब उपस्थित थे। सभी ने एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि सभी अपनी मां के नाम

से एक पेड़ लगाएं। उनके आह्वान पर यह एक आंदोलन बन गया है, हम लोग छत्तीसगढ़ में भी इसको अभियान के रूप में ले रहे हैं और अकेले वन विभाग का 4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के 33 जिलों में वन विभाग द्वारा 6 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। बहुत सी प्रजातियों के पेड़ लगाए जा रहे हैं। पीपल का पेड़ जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, नीम का पेड़, हरि बहेड़ा आंवला जैसे गुणकारी पौधे लगाए जा रहे हैं हर किसी को पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है आप सब लोग देख रहे हैं कि पेड़ कम होने से गर्मी के दिनों में गर्मी बहुत बढ़ रही है इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पूरे देश में पड़ी है। पारा 50 डिग्री पहुंच गया। पूरे विश्व में गर्मी से मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है, ऐसे समय में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम सभी पेड़ लगाएं। आज वृक्षारोपण अभियान में हमारे स्कूली बच्चे शामिल हुए, हमारे सीआरपीएफ के जवान शामिल हुए, हमारे वन और पुलिस विभाग का अमला भी शामिल हुआ। इन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों से भी आह्वान किया है कि बच्चे अपने स्कूल परिसर में अपनी मां के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाएं।

एक पेड़ मां के नाम अभियान रथ को मंत्री देवांगन ने हरी झंडी दिखाकर किया रावाना

कोरबा। वाणिज्य, उद्योग, व्यापार एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान रथ को आज कलेक्टर परिसर से हरी झण्डी दिखाकर रावाना किया। यह अभियान रथ के माध्यम से वन मंडल कोरबा अंतर्गत आमजनों को निःशुल्क पौधों प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद, कलेक्टर श्री अजीत वसंत, वनमण्डलाधिकारी कोरबा श्री अरविंद पीएम., मुख्य कार्यपालन अधिकारी



जिला पंचायत श्री संवित मिश्रा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे। एक पेड़ मां के नाम

अभियान रथ को रावाना करने के पूर्व कलेक्टर परिसर में मंत्री श्री देवांगन ने आम नागरिकों, कर्मचारियों को फलदार एवं

पेड़/पौधा मां के नाम पर अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी मां को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं

इसलिए उसके नाम पर लगाए गए पौधे के प्रति सजग रहेंगे और उसके विकसित होने तक देखभाल भी करेंगे। इससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक नगरी कोरबा में विभिन्न औद्योगिक संस्थान हैं जिससे निकलने वाले धुंएँ से पर्यावरण प्रभावित होता है। प्रदूषण से पेड़ पौधे ही बचा सकते हैं। इस दृष्टि से कोरबा नगर में वृक्षारोपण का महत्व और भी बढ़ जाता है।

दुष्कर्म मामले में रिपोर्ट नहीं लिखने पर कोमाखान टीआई निलंबित

पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कांग्रेस नेता को किया गिरफ्तार

महासमुंद्र। दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट नहीं लिखना टीआई को महंगा पड़ गया। पीड़िता की शिकायत के बाद एएसपी ने तत्काल कोमाखान थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। इधर अधिकारी पर कार्रवाई की खबर मिलते ही आनन-फानन में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, दुष्कर्म की पीड़िता एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोमाखान थाना पहुंची थी। उसने कांग्रेस नेता उतम राणा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, मगर उसे काफी देर बिठाने के बावजूद

एफआईआर नहीं लिखी गई। पीड़िता ने इसकी शिकायत टीआई शैलेन्द्र नाग से की, मगर उन्होंने भी पीड़िता को चलता कर दिया।

पीड़िता युवती ने एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सोधे एसपी आशुतोष सिंह से मुलाकात की और कोमाखान थाने के टीआई के खिलाफ शिकायत करते हुए उसकी एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस शिकायत पर एफआईआर काफी नाराज हुए और उन्होंने अपने अधीनस्थों को तत्काल टीआई के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया। टीआई द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने की पुष्टि होने के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से टीआई शैलेन्द्र नाग को सस्पेंड कर दिया।

सीएसपीडीसीएल के प्रबंध संचालक बनाए गए भीम सिंह कंवर

रायपुर। राज्य शासन ने भीम सिंह कंवर को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का संचालक एवं प्रबंध संचालक नियुक्त किया है। ऊर्जा विभाग ने प्रबंध संचालक बनाए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। भीम सिंह कंवर अभी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक (संचालन/संभारण) हैं। जारी आदेश के अनुसार भीम सिंह कंवर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 1 वर्ष अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, अस्थायी रूप से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

मनोज साहू बने टिकरापारा थाना के नए थाना प्रभारी, दुर्गेश रावटे लाईन अटैच

रायपुर। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना प्रभारी दुर्गेश रावटे लाईन अटैच कर दिए गए हैं। उनकी जगह निरीक्षक मनोज साहू को टिकरापारा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। एसएसपी रायपुर संतोष कुमार सिंह ने इसका आदेश जारी किया है।

ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में बाल-बाल बचे भाजपा नेता प्रबल प्रताप जूदेव



क्षतिग्रस्त हो गई है।

यह हादसा मुंगेली जिले के सरगांव के पास रायपुर से बिलासपुर जाते वक्त हुआ है। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक और चालक राम गणेश यादव (34) को गिरफ्तार कर लिया है।

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता स्व. दिलीप सिंह जूदेव के छोटे बेटे व कोटा विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव सड़क हादसे में बाल-बाल बचे। मिली जानकारी के अनुसार मवेशी को बचाने के दौरान अनियंत्रित होकर ट्रक ने गाड़ी को पीछे से ठोकर मारी है, जिससे प्रबल प्रताप जूदेव को हल्की चोट आई है। वहीं कार

बलौदाबाजार हिंसा ,एसआईटी की जांच तेज

आरोपी को घटना स्थल ले जाकर कर रही पूछताछ

ब लौ द ा बा ज ा र । बलौदाबाजार पुलिस की एसआईटी टीम 10 जून को ग्राम महुकोनी स्थित अमर गुफा में जैतखाम काटे जाने और उसके बाद बलौदाबाजार में हुए प्रदर्शन, हिंसा, लूटपाट व आगजनी मामले को लेकर लगातार कार्यवाही कर रही है। पुलिस की एसआईटी टीम आज



भीम आर्मी के बलौदाबाजार के किशोर नवरंग को दशहरा मैदान प्रदर्शन स्थल लेकर पहुंची और विस्तार पूर्वक पूछताछ कर प्रदर्शन स्थल का जायजा लिया और आरोपी से पूछताछ की। राज्य शासन ने पूरे घटना के निष्पक्ष जांच के निर्देश दिया है, जिसके बाद एसपी विजय

अग्रवाल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के नेतृत्व में एएसआईटी टीम जांच में लगी हुई है। पुलिस मामले में अब तक 159 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है।

2 महीने से लापता है छत्तीसगढ़ का अग्निवीर, जयपुर के बटालियन में था पदस्थ

मुंगेली। अग्निवीर में नियुक्त मुंगेली का जवान विगत 2 महीने से रहस्यमयी तरीके से लापता है। परियोजना उसकी पतासाजी के लिए लगातार विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल पा रहा है। वर्ष 2023 में मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के गोइन्द्री गांव का रहने वाला जवान राकेश कुमार निषाद की नियुक्ति अग्निवीर योजना में हुई थी। महाराष्ट्र के नासिक में 8 महीने की प्रशिक्षण के बाद जयपुर SATA बटालियन में अक्टूबर 2023 को उसकी पदस्थापना हुई थी। होली त्योहार पर राकेश अपने गांव छुट्टी पर आया हुआ था लेकिन वापसी होने के बाद अपने घर परिवार वालों से मोबाइल संपर्क पर रहा लेकिन अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया। जिसके बाद से परिवार वालों का उससे संपर्क बंद हो गया था। युवक के परिजनों ने जयपुर के अधिकारियों से संपर्क किया तब वहां के अधिकारियों ने उन्हें काल के माध्यम से बताया कि वह सेंटर से दीवार फांदकर भाग गया है और उसकी फाइल नासिक भेज दी गई है। इसलिए वह नासिक में संपर्क करें।

एशिया के सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाली जिला को मिले सुविधा

किसान कल्याण समिति की ओर से कलेक्टर के बाद सांसद और विधायक को लिखा पत्र

कोरबा/दीपका। जिला खनिज संस्थान न्यास निधि मद से कोरबा जिले के दीपका में माइनिंग कालेज की स्थापना की मांग करते हुए, ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति की ओर से सांसद और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिष्ना महंत और विधायक प्रेमचंद पटेल को पत्र लिखा गया। इससे पूर्व कलेक्टर, मुख्यमंत्री को भी जापान सौंपा गया था। ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष संपूर्ण कुलदीप ने अपने पत्र में मांग करते हुए बताया है कि कोरबा जिला में एस ई सी एल की संचालित कोरबा कोलफील्ड्स कोरबा, गेवरा, दीपका और कुसमुंडा क्षेत्र कोल इण्डिया की सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र है लगभग 60 सालों से कोरबा जिले में कोयला का रिकार्ड तोड़ उत्पादन हो रहा है। और एस ई सी एल की दो राज्यों में फैले कुल 13 क्षेत्रों में



से कोरबा कोलफील्ड्स के 4 क्षेत्र में ही सर्वाधिक उत्पादन होता है। एसईसीएल में विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 167.01 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है जिससे 33321.84 करोड़ रुपये का राजस्व

प्राप्ति हुए। जिससे सरकारी खजाने में 14,450 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया है। जबकि सम्पूर्ण एस ई सी एल की कुल उत्पादन की तुलना में कोरबा कोलफील्ड्स का उत्पादन का योगदान 135.27 मिलियन टन का रहा है 7 कोरबा जिले के चारों क्षेत्रों में कुल 12 खदानें संचालित हैं। और इन खदानों के

लिए हजारों किसानों की भूमि अर्जित किया गया है। किन्तु जमीन खोने वाले परिवारों को उनका वाजिब अधिकार, मुलभूत सुविधायें तक नसीब नहीं हो रहा 7 कोरबा जिला में उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने की योजना पर अब तक सार्थक पहल नहीं होने से यहाँ के विद्यार्थियों को अन्य जिलों अथवा

राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ तक की इतनी बड़ी-बड़ी कोयला खदान होने के बावजूद कोलेज तक नहीं है। यही कारण है, कि कोयला खदान में रोजगार के अवसर होने पर भी यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। जिला खनिज संस्थान न्यास निधि का गठन होने के बाद सही क्रियान्वयन भी नहीं हो रहा है। उसमें माइनिंग कालेज की स्थापना की मांग आरम्भ हो रही, अतः आपसे अनुरोध है, कि कोरबा जिले में माइनिंग कालेज की स्थापना कर बच्चों की पढ़ाई लिखाई आरम्भ करवाया जाए। और इस कालेज में जिले के भूविस्थापितों के बच्चों को विशेष आरक्षण और मुफ्त शिक्षा प्रदान करवाया जाए 7 जिससे कोरबा जिले के बच्चों की भी सुविधा मिलने पर आसानी से माइनिंग क्षेत्र में जाने का अवसर प्राप्त हो (ऊर्जाधानी मा इ नि ं व कोलेज तक नहीं है। यही कारण है, कि कोयला खदान

मुख्यमंत्री ,कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से मांग किया जा चुका है। आवश्यकता होने पर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा ताकि कोरबा वासियों को इसका लाभ मिल सके ।

केदार कश्यप को मिला संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार



सदन में पक्ष-विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात कही

रायपुर। वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नई जिम्मेदारी पर मंत्री ने सदन में पक्ष-विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात कही।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त प्रभार

मुझे सौंपा है। विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सदन की कार्यवाही को गति प्रदान करूंगा। संयुक्त रूप में अपना पक्ष रखूंगा। विपक्ष के साथी, नेता प्रतिपक्ष, सभी के साथ मिलकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी बात रखेंगे। अनेक विषय आएंगे, सरकार की ओर से उसका जवाब दूंगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ पूरे मंत्रिमंडल के अयोध्या प्रवास और रामलला के दर्शन पर केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का वहां जाना तय हुआ है। समय क्या रहेगा, यह तय होगा। राम मंदिर दर्शन योजना से पहले से हैं। लोगों को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो ही रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पूरा मंत्रिमंडल जाएगा अयोध्या, करेंगे रामलला के दर्शन



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट साथियों के साथ कल शनिवार 13 जुलाई को रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम साय और सभी मंत्री चार्टर्ड विमान से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। यह जानकारी राजस्व, आपदा

एवं खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने दी है। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव के साथ सभी कैबिनेट मंत्री कल अयोध्या जा रहे हैं। भगवान राम जी के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। निर्धारित शेड्यूल तय अभी नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, कल

सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित सभी कैबिनेट मंत्री प्राइवेट प्लेन से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। दर्शन करने के बाद देर शाम राजधानी रायपुर वापस लौट आएंगे। बता दें कि भाजपा ने अपने विधानसभा के घोषणा पत्र में रामलला दर्शन योजना का उल्लेख किया था और सरकार बनने पर इस योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लोग लगातार अयोध्या का दौरा कर रामलला के दर्शन कर रहे हैं।

24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस

पीसीसी चीफ बैज ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल



रायपुर। प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन नहीं, जंगल राज है। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था को लेकर 24 जुलाई को विधानसभा घेराव करने का एलान किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता में प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था बेहद खराब हो चुकी है। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। गुहमंत्रों का गृह क्षेत्र कवर्धा अपराध का गढ़ बन गया है। पुलिस का

पीसीआर वैन वसूली वैन बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सली उन्मूलन के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा, मारा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि मेरा एक साल का कार्यकाल चुनाव का कार्यकाल रहा है। एक साल में दो बड़े चुनाव हुए। विधानसभा और लोकसभा में हार मिली है। जो कमियां रही हैं, उसे दूर करेंगे। जनता का जनादेश कांग्रेस के साथ नहीं था, लेकिन हम आगे पूरी मजबूती से काम करेंगे।

प्रावधानों के तहत सफाई कर्मियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाएं -एम. वैंकटेशन

अध्यक्ष ने सफाई कर्मियों से वन टू वन चर्चा कर जानी उनकी समस्याएं

कोरबा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्ष श्री एम. वैंकटेशन ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सफाई कार्य से जुड़े विभागीय अधिकारियों, सार्वजनिक उपक्रम बाल्को, एनटीपीसी, एसईसीएल सहित अन्य उपक्रमों के अधिकारी की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सफाई कार्य कराने वाले एजेंसी के संचालकों, ठेकेदारों और संबंधित सफाई कर्मियों से चर्चा कर सफाई कर्मचारियों को दी जा रही वेतन, सफाई सामग्री, यूनिफॉर्म, सुरक्षा उपकरण, पीएफ, ईएसआईसी कार्ड के संबंध में जानकारी ली। अध्यक्ष श्री वैंकटेशन ने निर्देशित किया कि सफाई कर्मचारियों को एजेंसी द्वारा एग्रीमेंट के तहत सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। एग्रीमेंट का पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध उन्होंने कार्यवाही के निर्देश भी दिए। उन्होंने सफाई कर्मियों का श्रम कार्ड बनाने तथा शासन द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी



सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों एवं सफाई कर्मचारियों यूनिफॉर्म के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए समस्याओं का नियमानुसार निराकरण करने की बात कही। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अध्यक्ष श्री वैंकटेशन ने नगर पालिक निगम कोरबा, एसईसीएल सहित अन्य क्षेत्रों में एजेंसी के माध्यम से सफाई करने वाले कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने नगर निगम अंतर्गत संबंधित संचालक/ठेकेदारों को निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ सफाई कार्य करने वाले कर्मचारियों को निर्धारित राशि

आईडी कार्ड प्रदान करने के निर्देश दिए। बैठक में सफाई कर्मचारी यूनिफॉर्म के प्रतिनिधियों द्वारा मिशन क्लीन सिटी में कार्य करने वाली स्वच्छता दीदी को समय पर वेतन एवं अवकाश नहीं मिलने की जानकारी दी गई। इस संबंध में निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई द्वारा बताया गया कि बैंक द्वारा केवाईसी की प्रक्रिया कराई जा रही थी। दस्तावेजों के अभाव में कुछ स्वच्छता दीदीयों को वेतन में विलंब हुआ है। इस संबंध में कलेक्टर श्री वसंत ने निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि संबंधित सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग आयोजित कर उन्हें महिने की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से स्वच्छता दीदीयों का डाटा प्रस्तुत कराया जाए।

उनके खाते में प्रदान करें। कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करने के साथ ही उन्हें पीएफ और बीमा का लाभ अवश्य दें। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को 07 दिवस के भीतर यूनिफॉर्म, रेशनकार्ड, सुरक्षा उपकरण, आदि की पूर्ति करने के निर्देश दिए।

बच्चों से पूछे सवाल, बाटी टॉफी देकर बढ़ाया उनका उत्साह, पढ़ाया जल संरक्षण का पाठ

कलेक्टर ने सुकली आंगनबाड़ी केंद्र में “एक पेड़ मां के नाम” के तहत रोपा आम का पौधा

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर श्री आकाश छिकरा ने शुक्रवार को नवागढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत सुकली की आंगनबाड़ी केंद्र में “एक पेड़ मां के नाम” के तहत आम का पौधा लगाया और ग्रामीणों, महिलाओं एवं बच्चों में पर्यावरण के प्रति जन-जागरूकता को लेकर संदेश दिया। इसके साथ ही “जल शक्ति से नारी शक्ति” अभियान के तहत जल संरक्षण की शपथ भी दिलवाई। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति देवी सिंह, सुकली सरपंच श्री भोजराम करियारे, महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों ने पौधरोपण किया। कलेक्टर श्री आकाश छिकरा ने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका के साथ ही पौधरोपण करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत जल शक्ति से नारी शक्ति अभियान से जुड़कर हम सभी मिलकर पानी के महत्त्व को समझ सकते हैं और आज की



पौड़ी के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, पानी का संचयन, रेनवाटर हार्वेस्टिंग तथा खराब पानी का अन्य उपयोग इत्यादि विषय पर जानकारी देकर जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए जरूरी है कि हम पानी को व्यर्थ न बहाए और दिनचर्या में छोटी छोटी चीजों में जल संरक्षण का ख्याल रखते हुए बचत करें। वृक्षारोपण करने के उपरान्त उन्होंने बच्चों से आंगनबाड़ी केंद्र में दी जा रही प्रारंभिक शिक्षा को लेकर जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने गौरव, करुणा, देवांश, करण, खुशी, मयंक आदि बच्चों से उनका नाम, गिनती, ए बी सी

डी, कविता एवं आंगनबाड़ी में दिए जा रहे पोषण आहार के बारे में पूछा। बच्चों ने प्रश्नों का जवाब दिया तो कलेक्टर श्री छिकरा ने खुश होकर उन्हें टॉफी बाटी। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुपोषित बच्चों, गर्भवती, शिशुवती माताओं के घरों में फलदार पौधों के रोपण का अभियान चलाने, बेटियों के नाम से भी वृक्षारोपण करने कहा।

तहसीलदार पर भ्रष्टाचार का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत

महासमुंद। जिले के उप तहसील झलप में 8 जुलाई को नायब तहसीलदार के साथ हुई मारपीट का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं आज झलप के ग्रामीण उप तहसील झलप में चल रहे भ्रष्टाचार की शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उप तहसील में पदस्थ तहसीलदार नामांतरण, आय, जाति, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि के लिए पैसे की मांग करते हैं, जो गलत है इसलिए हम लोग आज कलेक्टर से शिकायत करने आए हैं। ग्रामीणों ने तहसीलदार को हटाने



की मांग की है। साथ ही उनके आय मांग उठाई है। गौरतलब है कि लोगों को शिकायत पत्र सौंपा और कुछ और संपत्ति की जांच कराने की भी ने कलेक्टर के नाम डिट्टी कलेक्टर लोगों ने तो शपथ पत्र बनवाकर



भी देना पड़ता था। अब जबकि इस छिंदई नदी में पुल बन गया है, ग्रामीणों का आवागमन आसान बन गया है। वे आसानी से घंटों की दूरी मिनटों में तय कर पहुंच जाते हैं।

करतला विकासखंड के ग्राम मदवानी -कछार-तराईमार -कुदमुरा मार्ग में छिंदई नदी में लगभग 17 करोड़ 17 लाख की राशि से बने उच्च स्तरीय पुल का हाल ही में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री

हो रही है। इस पुल के बन जाने से विकास के नए द्वार खुल गए हैं। वर्षों से इस नदी में पुल की मांग थी जो अब पूरी हो गई है। इससे आसपास के अनेक गांव

जुड़ गए हैं। एक दूसरे से सम्पर्क भी बढ़ गया है। यह पुल आवागमन का पुल होने के साथ ही विकास का भी पुल बन गया है। इस पुल को पार करते हुए ग्रामीण कमल सिंह चौहान ने बताया कि पहले उन्हें लंबी दूरी तय करके एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। उन्हें पांच से 10 किलोमीटर अतिरिक्त वाहन बाइक घुमाना पड़ता था। इससे उनके अतिरिक्त रूपये और समय का नुकसान होता था। उन्होंने बताया कि गर्मी के दिनों में नदी में पानी कास्तर कम होने पर बहुत से ग्रामीण जोखिम उठाकर नदी पार कर लेते थे। बारिश में नदी का स्तर बढ़ने पर पुल पार करना खतरनाक बन जाता था। अब

शिकायत की है। ग्रामीणों की शिकायत पूरी तरह झूठ -नायब तहसीलदार इस मामले में नायब तहसीलदार युवराज साहू का कहना है कि जो शिकायत झलप के लोग कर रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। मेरे साथ मारपीट होने के बाद वह इस तरह का शपथ और शिकायत कर रहे हैं। यदि ऐसा कुछ था तो वह पूर्व में भी इसकी शिकायत कर सकते थे। यदि ऐसी उनकी शिकायत है तो बिल्कुल जांच कर इस पर कार्रवाई शासन कर सकता है।

चीफ जस्टिस सिन्हा ने न्यायिक कर्मचारी आवासीय कालोनी का किया लोकार्पण

बिलासपुर। मुख्य न्यायाधिपति, श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा न्यायाधीश व पोर्टफोलियो जस्टिस जिला बेमेतरा द्वारा वर्चुअल माध्यम से जिला बेमेतरा में न्यायिक कर्मचारियों के आवासीय कालोनी सिंधौर व तहसील साजा में एवं बेमेतरा जिला न्यायालय परिसर में भारतीय उप डाकघर का लोकार्पण किया गया। चीफ जस्टिस द्वारा प्रशासन को कर्मचारियों के लिए सुन्दर, गुणवत्ता वाले आवास बनाये जाने पर बधाई दी गयी।

ग्राम विकास में सरपंच- सचिव की अहम भूमिका- कलेक्टर

कलेक्टर ने सरपंच - सचिव व जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक

कसडोल। कलेक्टर दीपक सोनी ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम गुरु घासीदास शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल कसडोल में सरपंच एवं सचिवों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सरपंच व सचिव का ग्राम विकास में अहम भूमिका बताते हुए विकास के दोनो मजबूत पाहियों को संतुलन बनाकर गति देने कहा।

कलेक्टर ने कहा कि अधोसंरचना निर्माण के साथ ही साथ स्थायी परिसम्पत्ति के निर्माण को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक डबरी निर्माण, खेल मैदान तथा सभी ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर का निर्माण



कराएं। उन्होंने महिला समूहों को जागरूक और सक्रिय कर आजीविकामूलक कार्य शुरू करने कहा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बल्दाकछार और औरई ग्राम में विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को पीएम आवास सहित सभी योजनाओं से शतप्रतिशत लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण

अवैधानिक कृत्य या रणनीति के संबंध में जानकारी मिलने पर तत्काल उच्च अधिकारी को या जिला कंट्रोल रूम नंबर 9479190629 पर सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। सरपंच सचिव विवाद या अन्य अवैधानिक गतिविधियों पर नजर रखें। अपने पंचायत को विवाद मुक्त ग्राम पंचायत बनाने का पूरा प्रयास करें। इसके लिए जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा।

नगर पंचायत कार्यालय कसडोल के सभाकक्ष में नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की गति देना है। किसी प्रकार की सम्बन्ध में गहन चर्चा की।



नए कानून संहिता के संबंध में आयोजित कार्यशाला में पत्रकारों को दी जानकारी

बलौदाबाजार। तीन नए अपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के विषय पर पुलिस कार्यालय सभाकक्ष बलौदाबाजार में पत्रकारों को जानकारी देने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार द्वारा नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए, नये कानून के तहत किए जाने वाले कार्य एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तार पूर्वक उपस्थित पत्रकारों को बताया गया। नए कानून में भारतीय दंड संहिता को अब भारतीय न्याय संहिता किया गया है, जिसमें विशेषता दंड से ज्यादा न्याय पर आ गया है।

अपराध होने से पहले ही रोकना और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना है। नवीन कानून बी.एन.एस. में प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी को किसी संगीन मामले की शिकायत मिलने पर प्रथम सूचना पत्र लिखने से पहले अपने उच्च अधिकारी से अनुमति लेकर प्राथमिक जांच करे। मतलब पुलिस अधिकारी को पर्याप्त समय मिलेगा, जिसमें वो तय करेगा कि मामले में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है या नहीं।

राजेश श्रीवास्तव उप पुलिस अधीक्षक ने नवीन तीनों कानून के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों तक नए कानून को जानकारी पहुंचाने में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस यानी मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि को सबूत के तौर पर परिभाषित किया गया है। किसी मामले की जांच, पुछताछ के दौरान माननीय न्यायालय या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति से डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या डिजिटल डिवाइस पेश करने के लिए समन या आदेश जारी कर सकता है। नए कानून के तहत जांच करने की शक्ति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को किसी मामले की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस मामले से जुड़े सबूतों, बयानों और वस्तुओं को भी इकट्ठा कर सकती है। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों द्वारा नए कानून के संबंध में कई प्रश्न पूछे गए, जिसमें उपस्थित पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।

अनियमितता, 3 खाद दुकानों को नोटिस

बलौदाबाजार। अनियमितता पर 3 खाद दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। विकासखण्ड-कसडोल के निरीक्षक, धनेश्वर साय द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कसडोल, संदीप कृषि सेवा केन्द्र बग्या, शिवम बीज भण्डार बग्या, भरत कृषि केन्द्र, उमा कृषि केन्द्र, अग्रवाल कृषि केन्द्र, गिधौरी, हनुमान कृषि केन्द्र कटगी का निरीक्षण किया गया। जिसमें हनुमान कृषि केन्द्र कटगी तथा भरत कृषि केन्द्र गिधौरी के द्वारा खोत प्रमाण पत्र का संधारण नहीं किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी तरह विकासखण्ड पलारी के निरीक्षक, सुचिन कुमार वर्मा द्वारा टी.एस. कृषि सेवा केन्द्र कोदवा, मेसर्स हीरालाल राजकुमार सण्डी, वर्मा कृषि सेवा केन्द्र सण्डी का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार विकासखण्ड-सिमगा के निरीक्षक रामअवतार राठौर द्वारा ओम कृषि केन्द्र सुहेला, देवा कृषि केन्द्र सुहेला का निरीक्षण किया गया तथा ओम कृषि सेवा केन्द्र सुहेला को स्टॉक एवं मूल्य सूची प्रदर्शित न करने तथा बिल बुक एवं स्टॉक रजिस्टर का उचित संधारण न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

पौने दो करोड़ में बनी पाथवे एक माह में ही धंस रही

बलौदाबाजार। जिला मुख्यालय में करीब पौने दो करोड़ की लागत से निर्मित पाथवे एक माह में ही जगह-जगह से धंस रही है।

इस संबंध में पालिका की उप अभियंता कमलेश्वरी गुरुपंचायन व सीएमओ खिरोद भोई के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो उन्होंने काल रिसीव नहीं किया। व्हाट्सएप पर संदेश भेजने के बावजूद भी दोनों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया।

गौरतलब है कि नगर पालिका बलौदाबाजार द्वारा पाथवे का निर्माण कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है। जिसमें मुख्य मार्ग के करीब तीन किलोमीटर दोनों किनारों पर पेवर् ब्लॉक लगाए जाने का कार्य शामिल है। यह



कार्य दो भागों में किया जा रहा है।

जून से ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ करते हुए कलेक्ट्रेट निवास से लवन रोड श्री राम ट्रेडर्स तक और रायपुर रोड से शुक्ला पयूस तक पेवर् ब्लॉक लगाने का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है। परंतु डेढ़ माह में ही नगर के अधिकांश हिस्से में लगाया

गया है ब्लॉक जगह-जगह से धंस अथवा उखड़ गया है। जिसमें बारिश का पानी आकर जमा हो रहा है। कई स्थानों पर ब्लॉक का ताल इतना नीचे है कि

रही है।

पार्श्व ही उठा रहे सवाल

गुणवत्ताहीन कार्य को लेकर कुछ पार्श्व व सभापति सोशल मीडिया में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कार्य के दोयम दर्जे का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि नया बस स्टैंड चौपाटी आरटीओ कार्यालय के सामने लवन रोड पर दुर्गा फयूज चंदा देवी चिकित्सालय के आसपास एसबीआई से लेकर जिला भाजपा कार्यालय सभापति संकेत शुक्ला के घर के करीब किसान राइस मिल परिसर रायपुर लवन रोड के सामने समय दर्जनों स्थान पर पेवर् ब्लॉक कई स्थान पर उखड़ गए हैं। जबकि साइड शोल्डर भी जगह-जगह टूट रहा है।

ध्वस्त हुआ अविश्वास प्रस्ताव, डोंगरगढ़ में कांग्रेस की बनी रहेगी शहर सरकार

डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद से डोंगरगढ़ नगर पालिका में सियासी उठापटक चल रही थी। कांग्रेस समर्थित पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान हुआ, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया।

अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जहां 15 पार्श्वों ने वोट किया तो वहीं प्रस्ताव के विपक्ष में 8 वोट पड़े, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए दो तिहाई बहुमत के तौर पर 16 पार्श्वों के वोट की जरूरत थी। फिलहाल कांग्रेस के सुदेश मेश्राम अपनी अध्यक्ष की कुर्सी बचाने में सफल रहे, जिसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है।

बता दें कि सत्ता परिवर्तन के बाद नगर पालिका उपाध्यक्ष उमा महेश वर्मा एक निर्दलीय पार्श्व के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद से लगातार कांग्रेस की शहर सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। भाजपा अपने पार्श्व दल के साथ कांग्रेसी पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, जो आज ध्वस्त हो गया।

भाजपा-कांग्रेस के 10-10 और 3 निर्दलीय पार्श्वों ने किया मतदान

24 वार्ड वाली डोंगरगढ़ नगर पालिका के पिछले



चुनाव में कांग्रेस के 11, भाजपा के 10 और तीन निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। निर्दलीय पार्श्व में से एक पार्श्व अनीता इंदुलकर जीतकर भाजपा में शामिल हो गईं, जिसके बाद स्थिति बराबर की हो गईं।

बाद में दो निर्दलीय पार्श्वों के सहयोग से कांग्रेस के सुदेश मेश्राम अध्यक्ष और निर्दलीय पार्श्व उमा महेश वर्मा को उपाध्यक्ष चुने गए, वर्तमान स्थिति में कांग्रेस पार्श्व की मृत्यु के बाद पालिका में अब 23 पार्श्व हैं, जिन्होंने आज नगर पालिका परिषद के सभा गृह में अध्यक्ष सुदेश मेश्राम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान किया।

संचालित महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह खाते में 1000 रुपए मिलने से महिलाओं को अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होती है। हितग्राही श्रीमती नायक ने कहा कि उनके पति श्री नीलांबर नायक खेती का कार्य करते हैं।

विगत 5 माह से उन्हें योजना के तहत राशि प्राप्त हो रही है। जिसका उपयोग वे अपने एवं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने, बच्चों के अध्यापन कार्य तथा उनके लिए पौष्टिक भोजन के व्यवस्था करने में करती हैं। साथ ही राशनकार्ड

से उन्हें निर्धारित दर पर खाद्यान्न भी प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि हर माह खाते में राशि जमा होने से महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही उन्हें एक प्रकार की वित्तीय सुरक्षा महसूस होती है।

बिहान से जुड़कर ग्राम पंचायत पलाड़ीकला में महिलाएं हुई सशक्त



सक्ति। सक्ती तहसील बाराद्वार जनपद पंचायत सक्ति बिहान से जुड़कर ग्राम पंचायत पलाड़ीकला में 40 महिला समूह में 420 महिलाएं जुड़ कर 2 संगठन बनाकर पैसे बचत कर सरकार द्वारा मिली अनुदान राशि, बैंक से ऋण लेकर महिलाएं स्वरोजगार को अपना कर महिलाएं हो रही हैं। आत्म निर्भर महिलाएं द्वारा विभिन्न प्रकार की आजीविका अपना कर अपने परिवार का भरण पोषण में कर रही सहयोग एवं आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएँ।

सक्ती तहसील बाराद्वार जनपद पंचायत सक्ति बिहान से जुड़कर ग्राम पंचायत पलाड़ीकला में 40 महिला समूह में 420 महिलाएं जुड़ कर 2 संगठन बनाकर पैसे बचत कर सरकार द्वारा मिली अनुदान राशि, बैंक से ऋण लेकर महिलाएं स्वरोजगार को अपना कर महिलाएं हो रही हैं। आत्म निर्भर महिलाएं द्वारा विभिन्न प्रकार की आजीविका अपना कर अपने परिवार का भरण पोषण में कर रही सहयोग एवं आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएँ।

सक्ती तहसील बाराद्वार जनपद पंचायत सक्ति बिहान से जुड़कर ग्राम पंचायत पलाड़ीकला में 40 महिला समूह में 420 महिलाएं जुड़ कर 2 संगठन बनाकर पैसे बचत कर सरकार द्वारा मिली अनुदान राशि, बैंक से ऋण लेकर महिलाएं स्वरोजगार को अपना कर महिलाएं हो रही हैं। आत्म निर्भर महिलाएं द्वारा विभिन्न प्रकार की आजीविका अपना कर अपने परिवार का भरण पोषण में कर रही सहयोग एवं आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएँ।

महतारी वंदन योजना से महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त

कोरबा / महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जगहैतैभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए की

आर्थिक मदद हर महीने सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में प्राप्त होती है। जिससे महिलाएं स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ सकें एवं अपनी सेहत एवं आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएँ।

भो इस योजना का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। कोरबा विकासखण्ड के कोरकोमा की रहने वाली श्रीमती गीता नायक ने योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि महिला



सशक्तिकरण की दिशा में यह एक सार्थक प्रयास है। योजना से मिलने वाली राशि जरूरतमंद महिलाओं के लिए मुश्किल वक का सहारा बनी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा

संचालित महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह खाते में 1000 रुपए मिलने से महिलाओं को अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होती है। हितग्राही श्रीमती नायक ने कहा कि उनके पति श्री नीलांबर नायक खेती का कार्य करते हैं।

विगत 5 माह से उन्हें योजना के तहत राशि प्राप्त हो रही है। जिसका उपयोग वे अपने एवं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने, बच्चों के अध्यापन कार्य तथा उनके लिए पौष्टिक भोजन के व्यवस्था करने में करती हैं। साथ ही राशनकार्ड

से उन्हें निर्धारित दर पर खाद्यान्न भी प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि हर माह खाते में राशि जमा होने से महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही उन्हें एक प्रकार की वित्तीय सुरक्षा महसूस होती है।

न्यूज़ रूटीन

संपादकीय

मुद्रास्फीति के विरोधाभासी रुख

एक मुद्रास्फीति कम हुई है, तो दूसरी महंगाई दर बढ़ी है। आप अर्चिषत न हों, क्योंकि महंगाई हमारे जीवन का अंतरंग हिस्सा बन गई है। सरकार मानने को तैयार नहीं है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) चिंतित है। अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट आई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर 4.83 फीसदी है, जो बीती मार्च में 4.85 फीसदी थी। हालांकि यह दर 11 माह के दौरान सबसे कम मुद्रास्फीति है। इसी दौरान खाने-पीने की वस्तुओं, अनाज, फल, सब्जियों, मांस-मछली आदि की खुदरा महंगाई दर बढ़ कर 8.70 फीसदी हो गई है। मार्च में यह 8.52 फीसदी थी। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को लक्ष्य दिया है कि मुद्रास्फीति 4 फीसदी रहनी चाहिए। उसमें अधिकतम 2 फीसदी की बढ़-घट हो सकती है। खुदरा मुद्रास्फीति सबसे कम है, लेकिन 4 फीसदी से अधिक है। अनाज की कीमतों में 8.63 फीसदी, फलों में 5.22 फीसदी, मांस-मछली में 8.17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अंडे, दालों, सब्जियों और मसालों की कीमतें कुछ कम हुई हैं। ये आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के हैं, जो मुद्रास्फीति की सरकारी स्थितियों का खुलासा करते हैं। अलबत्ता खुले और बेलगाम बाजार की कीमतें कुछ और ही होंगी, लिहाजा मुद्रास्फीति उन्हीं के मुताबिक तय होगी। कुछ सर्वेक्षणों में 22 अर्थाशास्त्रियों ने अप्रैल माह में खुदरा महंगाई के 4.87 फीसदी पर स्थिर रहने का अनुमान जताया था। उनका कहना था कि मार्च के बाद से खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है, जो काफी हद तक मौसमी है।

क्रिस्टिल ने अपनी रपट में कहा है कि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, जून तक तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावनाएँ हैं, जिसका असर सब्जियों के उत्पादन पर पड़ेगा। नतीजतन अगले कुछ माह तक सब्जियां महंगी रह सकती हैं। दिलचस्प है कि देश में लोकसभा चुनाव जारी हैं। औसतन हर सर्वेक्षण में बेरोजगारी के बाद महंगाई दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। मतदाता भी सड़कों पर आंदोलित दिखाई दिए हैं। देश के औसत और कामगार तबके में, महंगाई के कारण, रोष भी दिखाई दिया है, लेकिन महंगाई चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है। हालांकि इस साल अच्छी बारिश होने की संभावनाएँ और अपेक्षाएँ हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम मानसून को 'सामान्य से ऊपर' आंका है। यदि ऐसा हुआ, तो कृषि-उत्पादन बेहतर होगा और कीमतें नियंत्रण में रह सकेंगी। गैर-खाद्य वर्ग में मुद्रास्फीति कपड़ा, जूते, घरेलू वस्तुओं, सेवाएं, मनोरंजन आदि वर्गों के मातहत रहती है। खाद्य मुद्रास्फीति से जुड़ी अनिश्चितताओं का एमपीसी पर भारी प्रभाव पड़ता है। खाद्य मुद्रास्फीति कई महीनों से 8 फीसदी से ऊपर चल रही है। एमपीसी की पिछली बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की टिप्पणी थी- एमपीसी को हर दम चौकस और जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि खाद्य कीमतों की अनिश्चितताएँ चुनौती देती रहती हैं। बहरहाल विश्व के प्रमुख विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों ने दरों में कटौती आरंभ करनी है। हालांकि कुछ घटनाएँ इस संभावना की ओर संकेत करती हैं कि इन देशों की नीतियों में विचलन हो सकता है। अमरीकी फेडरल रिजर्व की मार्च में हुई बैठक में पाया गया कि मुद्रास्फीति के मोर्चे पर प्रगति का अभाव है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3.2 फीसदी से बढ़कर 3.5 फीसदी हो गया। मंथन किया गया कि दरों में कटौती कब और कितनी करनी चाहिए। यह हमारे रिजर्व बैंक की एमपीसी की भी चिंता है। रिजर्व बैंक ने 2024-25 में 4.5 फीसदी मुद्रास्फीति का आकलन किया है, लेकिन खाद्य कीमतों में पर्याप्त अनिश्चितता रहेगी, एमपीसी ने यह अनुमान भी लगाया है। संभव है कि अर्थशास्त्र की यह भाषा पाठकों को समझ न आए अथवा कम समझ आए, लिहाजा हम स्पष्ट कर दें कि महंगाई काबू करने पर अभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार या बैंक के विचाराधीन नहीं है। देश में सबसे अधिक मुद्रास्फीति का दौर इंदिरा गांधी की सरकार में रहा है।

बुजुर्गों के बीमे के सच



प्रधानमंत्री मोदी की एक चुनावी गारंटी है कि अब 70 वर्ष की उम्र या उससे अधिक के प्रत्येक नागरिक को 'आयुष्मान' योजना का लाभ मिलेगा। वे 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त ही करा सकेंगे। यदि प्रधानमंत्री की भावना वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवर देने की थी, तो इस आयु-वर्ग के दायरे में 65 साल के वरिष्ठ नागरिक भी रखे जा सकते थे, क्योंकि इस उम्र तक बीमारियां पकने लगती हैं और इलाज की सख्त जरूरत होती है। इस सूची में मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर, किडनी, प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियां रखी जा सकती हैं, जो उम्र के साथ-साथ बढ़ते लगती हैं। यदि प्रधानमंत्री ने ऐसा किया होता, तो न केवल देश के बुजुर्ग उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते, बल्कि सकल जीवन प्रत्याशा भी बढ़ती। दरअसल बूढ़ों को स्वास्थ्य कवर देना बेहद गंभीर और जरूरी मुद्दा है, क्योंकि स्वास्थ्य बीमा कंपनियां वरिष्ठ नागरिकों को कवर देने से कन्नी काटती हैं या साफ इंकार कर देती हैं। अधिकतर निजी कंपनियों के बीमे की किस्त बेहद महंगी होती है, जिसे बिना पेंशन वाले बुजुर्ग वहन नहीं कर सकते। जो सरकारी सेवाओं में रहे हैं, उनके लिए सोजीएचएस जैसी सुविधाएं ताउम्र उपलब्ध हैं। ऐसे बहुत कम फीसदी लोग हैं। आम आदमी के लिए बीमा कंपनियों की शर्तें इतनी महीन छपी जाती हैं कि उन्हें पढ़ना असंभव होता है, लिहाजा बीमा लेने वालों को एजेंट के कथनों पर ही भरोसा करना पड़ता है। सरकारी डाटा ही खुलासा करता है कि मात्र 6 फीसदी आबादी उन वरिष्ठ नागरिकों की है, जिनके पास अपना स्वास्थ्य बीमा कवर है, जबकि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडाई) बुजुर्गों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता रहा है। यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन संसद में पारित बिल के जरिए किया गया था, ताकि बीमा बाजार पर निगाह रखी जा सके। इसके वावजूद देश और समाज के सबसे संवेदनशील समूह को बीमे के फायदों और जरूरत से बाहर रखा गया है, क्योंकि बीमे की किस्त वाकई बेहद महंगी है।

प्रधानमंत्री की गारंटी 'मास्टर स्ट्रोक' साबित हो सकती थी। इरडाई का ही डाटा है कि 144 करोड़ के देश में 55 करोड़ के पास ही स्वास्थ्य कवर है। औसतन 100 में से 54 कवर सरकार द्वारा प्रायोजित होते हैं। किस्त के तौर पर कमाए गए प्रति 100 रुपए में से 91 रुपए व्ययकित और समूह बीमा पॉलिसी से आते हैं। 'पॉलिसी बाजार' नामक बीमा कंपनी के सर्वेक्षण के मुताबिक, देश में 96 फीसदी लोग स्वास्थ्य बीमा जानते हैं, लेकिन 43 फीसदी ने ही पॉलिसी ले रखी है।

डा. जयंतीलाल भंडारी

इन दिनों प्रकाशित हो रही विदेश व्यापार संबंधी नई रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि 4 जून के बाद गठित होने वाली भारत की नई सरकार की यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह भारत की सेवा निर्यात (सर्विस एक्सपोर्ट) में दिखाई दे रही ऊंची संभावनाओं को साकार करके बढ़ते विदेश व्यापार घाटे को कम करने की ड्यार पर आगे बढ़े। साथ ही सेवा निर्यात बढ़ाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित नए डिजिटल कौशल से दक्ष देश की नई पीढ़ी के लिए रोजगार के नए मौके भी तेजी से निर्मित करके नई पीढ़ी को नई मुस्कुराहट दे। गौरतलब है कि कल तक पूरी दुनिया में भारत का सेवा निर्यात तेज रफ्तार से बढ़ रहे चमकीले सेक्टर के रूप में रेखांकित होता रहा है, लेकिन अब भारत के इसी प्रभावी सेवा निर्यात ने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सुस्त रफ्तार दिखाई है। सेवा निर्यात की यह रफ्तार पिछले तीन साल में सबसे कम रही है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से माल एवं सेवाओं का कुल निर्यात 776.68 अरब डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 776.40 अरब डॉलर रहा था। ऐसे में गत वित्त वर्ष में सेवा निर्यात 3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 339.62 अरब डॉलर का रहा, जबकि वस्तु निर्यात 3.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 437.06 अरब डॉलर रहा है। निश्चित रूप से बीते कुछ वर्षों में भारत के निर्यात का एक चमकदार पहलू सेवा निर्यात रहा है। भारत ने डिजिटल माध्यम से हुंहाय करायी गयीं सेवाओं के निर्यात में वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। डिजिटल माध्यम से सेवा निर्यात के तहत कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर शिक्षा, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, गेमिंग, मनोरंजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पायथन वर्चुअल रियल्टी, रोबोटिक प्रोसेस, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिसिस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, ब्लॉक चेन और सायबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवाओं को कुशल बनाना होगा

आदि के लिए दक्ष ऑपरेटर, कुशल प्रोग्रामर और कोडिंग विशेषज्ञ द्वारा दी जाने वाली सेवाएं शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित एक शोध आलेख के पिछले तीस वर्षों में यानी 1993 से 2022 के बीच भारत का सेवा निर्यात 14 फीसदी से अधिक की समेकित सालाना वृद्धि दर से बढ़ा। यह 6.8 फीसदी की वैश्विक सेवा निर्यात वृद्धि की तुलना में बेहतर है। परिणामस्वरूप समान अवधि में सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.5 फीसदी से बढ़कर 4.3 फीसदी जा पहुंची। इसी आधार पर भारत दुनिया में सातवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश बन गया है, जबकि वर्ष 2001 में सेवा निर्यात के मामले में भारत 24वें स्थान पर था। खास बात यह भी है कि दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात के क्षेत्र में भारत दुनिया में दूसरे और सांस्कृतिक तथा मनोरंजक सेवा निर्यात में छठे स्थान पर है। विश्व व्यापार संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार यदि केवल डिजिटल माध्यम से जुड़ी हुई सेवाओं के निर्यात के आधार पर मूल्यांकन करें तो इस क्षेत्र में भारत तेरमनी और चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड के बाद चौथे क्रम पर आ गया है। निश्चित रूप से भारत सेवाओं के निर्यात में वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। निस्संदेह भारत में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल कैपिटलिटी सेंटर (जीसीसी) की तेजी से नई स्थापनाओं के कारण भी सेवा निर्यात बढ़ रहा है। यह कोई



छोटी बात नहीं है कि वर्ष 2015-16 से लगातार वर्ष 2022-23 के बीच भारत में जीसीसी की संख्या 60 फीसदी बढ़कर 1600 से अधिक हो गई है। जीसीसी भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित विशेष केंद्र हैं जिनका मकसद स्थानीय प्रतिभा का फायदा उठाना, अधिक से अधिक परिचालन दक्षता हासिल करना और नए बाजारों तक पहुंचना है। जीसीसी सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), वित्त, मानव संसाधन, ग्राहक सेवा, विश्लेषण और कारोबारी प्रक्रियाओं के संचालन सहित तमाम क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि भारत में जीसीसी की आय पिछले 13 वर्षों में 11.4 फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक दर (सीएजीआर) से बढ़ी और चार गुना होती हुई वित्त वर्ष 2023 में 46 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बीते कुछ दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था का अहम पहलू सेवा निर्यात रहा है। इसने न केवल व्यापार घाटे को थामे रखने में मदद की है, बल्कि इससे देश में रोजगार निर्माण में सहारा दिया है। भारत ने वैश्विक सेवा व्यापार में प्रतिस्पर्धी क्षमता भी प्रदर्शित की है। दूरसंचार और सूचना

प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में भारत की लगातार पहचान बढ़ी है। लेकिन अब सेवाओं के निर्यात में कमजोर वृद्धि की मुख्य वजह विविध अर्थव्यवस्थाओं से मांग नरम रहना है।

वित्त वर्ष 2024-25 में भी सेवा निर्यात की हालत कमजोर ही रहने की आशंका है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था और विशेष तौर पर अमेरिका एवं यूरोप में उच्च ब्याज दरों के कारण मांग में नरमी रहेगी तथा युद्धजनित परिस्थितियों से वैश्विक व्यापार में कमी आएगी। निश्चित रूप से जिस तरह से ईरान-इजराइल के बीच टकराव और दुनिया में भूराजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, उससे कच्चे तेल के दाम के साथ-साथ आपूर्ति संकट बढ़ने की चिंताएं मुंहबाए खड़ी हैं। इससे भारत के वैश्विक व्यापार व निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में भारत को सेवा निर्यात बढ़ाने की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। चूंकि इस समय विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश अपने टट के आसपास के देशों में कारोबार पर जोर दे रहे हैं, यह भारतीय निर्यातकों के लिए भी चुनौती है।

लेकिन यह बात ध्यान में रखी जानी होगी कि अब सेवा निर्यात के क्षेत्र में भी लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भारत से डिजिटल सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता तथा सुरक्षा को लेकर और अधिक

आर्थिक मोर्चे पर भारत का सुनहरा भविष्य

अंश चतुर्वेदी

इसे संयोग ही कहेंगे कि जिस समय भारतीय चुनाव अभियान के दौरान विपक्षी दल महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ साल 2024 में भारत में मुद्रास्फीति साढ़े चार फीसद रहने का अनुमान जता रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट में जताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अनुमान रिपोर्ट में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

भारत के लिए निश्चित तौर पर यह अनुमान सुखद और उत्साहित करने वाला है। इसकी वजह यह है कि दुनिया की विकसित कहीं जाने वाली ज्यादातर पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में लगातार गिरावट जारी है। पश्चिमी मुक्तकों की अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर कमजोर होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में पड़ोसी चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन वह अब गिरने लगी है। विश्व बैंक ने मौजूदा साल में उसकी अर्थव्यवस्था में महज साढ़े चार प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था, हालांकि अब उसमें उसने थोड़ा सुधार करके उसे 5.2 प्रतिशत की बढ़त का अनुमान लगाया गया है।

आखिर भारत में यह बदलाव क्यों हो रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था इस तरह अग्रसर क्यों है? इसकी मोटी वजह यहां तेजी से विकसित हो रहा बुनियादी ढांचा है। बुनियादी ढांचे में भारत ने निवेश लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही भारत में निर्माण गतिविधियां भी तेज हैं। यह भी सच है कि भारत के लिए यहां की बेतहाशा बढ़ी जनसंख्या भी चुनौती बन रही है। लेकिन इसके साथ ही कुछ सत्य यह है कि बढ़ती जनसंख्या के चलते उपभोक्ता बाजार तेजी से बढ़ता

आखिर भारत में यह बदलाव क्यों हो रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था इस तरह अग्रसर क्यों है? इसकी मोटी वजह यहां तेजी से विकसित हो रहा बुनियादी ढांचा है। बुनियादी ढांचे में भारत में निवेश लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही भारत में निर्माण गतिविधियां भी तेज हैं।

है। उसमें खपत के लिए निर्माण और उत्पाद का दायरा बढ़ता है। यह पूरी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाती है और इस तरह जीडीपी में बढ़ोतरी होती है। 140 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया है। इसकी वजह से भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार तैयार है। इस बाजार में खपत के लिए तमाम तरह के उत्पादों की जरूरत बढ़ी है। जनसंख्या, उत्पादन, खपत और बाजार की कड़ियां इस तरह भारत में तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए भारतीय जीडीपी में तेजी आ रही है।

बाजार लाख बढ़ा हो, अगर सरकारी नीतियां उपभोक्ता, उत्पादक, खरीददार और विक्रेता के बीच संतुलन के साथ ही नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाली नहीं होती तो आर्थिक गतिविधियां तेज नहीं होती। इस संदर्भ में मोदी सरकार की भी श्रेय दिया जाना चाहिए, जिसने भारतीयता की सोच के साथ देसी दुनिया को वैश्विक आधारों से जोड़ने के साथ ही भारत को उत्पादन का हब बनाने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया है। नीतियों का ही असर है कि भारत में साल 2014 की 350 की तुलना में इन दिनों एक लाख तीस हज़ार स्टार्ट अप हैं। जिनमें युनिकार्न यानी एक अरब की पूंजी वाले स्टार्टअप की संख्या सौ से ज्यादा है। इसके साथ ही सात में पहली बार जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर से वसूली 2 लाख करोड़ रुपये के पार हो गई है। मौजूदा साल के अप्रैल में कुल जीएसटी वसूली 2.1 लाख करोड़ रुपये रही, जो साल 2023 के अप्रैल के

मुकाबले 12.4 फीसद ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान घरेलू लेन-देन का रहा, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 13.4 फीसद बढ़ गया। पिछले साल अप्रैल में सरकार को 1.87 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी वसूली हुई थी।

वित्त मंत्रालय के एक मई को बताया कि रिफंड के बाद अप्रैल महीने की शुद्ध जीएसटी



वसूली 1.92 लाख करोड़ रुपये रही है। जो इसी पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 17.1 प्रतिशत ज़्यादा है। साल 2017 में जबसे जीएसटी कानून लागू हुआ है, हर साल इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। जीएसटी लागू होने के फौरन बाद 2017-18 में जहां औसत जीएसटी एक लाख करोड़ रुपये से कम रही, वहीं, कोरोनाकाल के बाद 2020-21 से यह लगातार बढ़ रही है। साल 2022-23 में जीएसटी वसूली औसतन 1.51 लाख करोड़ रुपये हर महीने रही है। यह बढ़ोतरी ही बताने के लिए एमपीसी ने अपनी नीतियों में आर्थिक गतिविधियां तेज रहती हैं। इसकी वजह से भी भारतीय आर्थिकी तेजी से आगे बढ़ती

प्रेरित योजनाएं लाने का वादा जरूर किया है। लेकिन यह भी सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह आगे बढ़ चुकी है, उसमें उनके लिए भी कुछ ज्यादा करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। उन्हें भी मौजूदा आर्थिक चलन के ही मुताबिक आगे बढ़ना होगा। भले ही वे जीएसटी को कम करने या उसका ढांचा सुधारने का वादा करते रहे हों, लेकिन

भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, संस्कृति और सभ्यता भी दुनिया की नजरों में और आकर्षक हो सकती है। इसकी वजह से नए तरह की उत्पादकता भी भारत में दिख सकती है। सभ्यता, संस्कृति, तीर्थाटन और पर्यटन के साथ ही भारतीय पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था और योग भारत की अनुपम संपत्ति हो सकते हैं। इसे देखते हुए भारत की मौजूदा सरकार ने देश के स्वास्थ्य ढांचा को पहले की तुलना में बेहतर करना शुरू किया है। कोरोना काल के हालात की वजह से पारंपरिक भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, भारतीय ज्ञान परंपरा, योग आदि की भी दुनिया में मांग बढ़ी है। दुनिया इनकी ओर उम्मीदधरी नजरों से देख रही है। इनकी वजह से भारत में विदेशों से धन भी आ रहा है। भारतीय तीर्थाटन की परंपरा को राम मंदिर, महाकाल मंदिर और विश्वनाथ कारीडोर जैसे नए मंदिरों और धार्मिक केंद्रों की ओर दुनियाभर से आ रहे श्रद्धालुओं की वजह से बुनियादी ढांचे और पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को इनके जरिए भी तेजी मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय पर्यटन केंद्रों की अभी तक पूरी तरह से वैश्विक पहचान और ध्यान नहीं मिल पाया है। इस क्षेत्र में अभी काम

को परंपरा को राम मंदिर, महाकाल मंदिर और विश्वनाथ कारीडोर जैसे नए मंदिरों और धार्मिक केंद्रों की ओर दुनियाभर से आ रहे श्रद्धालुओं की वजह से बुनियादी ढांचे और पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को इनके जरिए भी तेजी मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय पर्यटन केंद्रों की अभी तक पूरी तरह से वैश्विक पहचान और ध्यान नहीं मिल पाया है। इस क्षेत्र में अभी काम

महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से लें प्रेरणा

आज भौतिकतावाद और जीवन की आधापाधी के बीच बौद्ध जीवन मार्ग और महात्मा बुद्ध के संदेशों का महत्व और बढ़ गया है। बुद्ध की शिक्षाएं प्रत्येक काल एवं परिस्थितियों में मानवमात्र का मार्गदर्शन करती आई हैं।

यही वजह भी है कि इनकी शिक्षाओं को विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के दृष्टिगत स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है जागा हुआ, एनलाइटेनड अर्थात् जिसे सत्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। यहां इसका तुच्छ अर्थ केवल राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ से नहीं है, बल्कि उनके पहले भी अनेक समाधिस्थ व्यक्तियों को चैतन्यता, सत्य और जीवन के रहस्यों से साक्षात्कार होने के कारण बुद्ध की श्रेणी में रखा गया है।

कोपाबेड़ा नगर वन में किया गया वन महोत्सव



कोडागांव। कोडागांव वन मंडल द्वारा नगर वन कोपाबेड़ा में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां नीम, जामुन आम, साल, इमली, अमरूद आदि पौधे रोपे गए। स्थानीय विधायक सुश्री लता उमंडी ने यहां पौधा रोपा और इस अवसर पर कहा कि वन से जीवन है, इसलिए वन का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के साथ ही उनका संरक्षण भी हम सभी का दायित्व है। 1%एक वृक्ष मां के नाम% से चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत हम सभी एक पौधा अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण करें।

कोडागांव वन मंडल द्वारा इस वर्ष लगभग दस लाख पौधे लगाए जाएंगे। इनमें दो स्थानों पर प्लांटेशन का कार्य के अंतर्गत 25 हजार पौधे रोपे जाएंगे। इसके साथ ही पूर्व वर्षों में किए गए वृक्षारोपण में क्षतिग्रस्त पौधों के स्थान पर 55 हजार नए पौधे लगाए जाएंगे। किसान वृक्ष मित्र योजना 8 लाख 68 हजार पौधे लगाए जाएंगे। वृक्ष प्रदाय योजना के अंतर्गत भी इमली, मूंगा, नींबू आम, आंवला अमरूद आदि पौधे निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

नगर वन में आयोजित वन महोत्सव में नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री जसकेतु उमंडी, वन मंडलाधिकारी श्री आर के जांगड़े, भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी श्री नवीन कुमार सहित जनप्रतिनिधिगण एवं वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, छात्र-छात्राएं तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

सर्पदंश होने पर कराए तत्काल चिकित्सा, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में है एंटी सैक वेनो इंजेक्शन

कोरिया। वर्षा ऋतु में सांप काटने की समस्या अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सांप के काटने पर उचित जानकारी के अभाव में लोग अक्सर झाड़ू-फूंक और ओझा पर विश्वास कर लेते हैं, जिससे कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.एस. सेंगर ने जानकारी दी है कि अप्रैल 2024 से अब तक सांप काटने की 80 प्रकरण आए हैं, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में एंटी सैक वेनो इंजेक्शन की व्यवस्था की गई है। आम लोगों को सर्पदंश के उपचार एवं प्रबंधन की उचित जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।

सर्पदंश होने पर क्या करें

सबसे पहले जिसे सांप ने काटा है, उसे धीरज दिलाएं, मरीज को स्थिर रखें, घाव को पानी से धोएं, घाव को साफ कपड़े से ढंक दें, कपड़े ढीले कर दें, आभूषण निकाल दें, हिलने-डुलने न दें, घाव के ऊपर-नीचे टोनिरकेट नहीं लगाएं, तुरंत अस्पताल ले जाएं।

सर्पदंश होने पर क्या न करें

व्यक्ति को बेहोश न होने दें। मरीज की झाड़ू-फूंक न करवाएं। जहां सांप ने काटा है, उस जगह पर न तो चौरा लगाएं और न ही जहर चूसें। काटने वाली जगह पर रूमाल, कपड़ा, रस्सी जैसा कुछ न बांधें। दर्द कम करने के लिए पेन किलर या अल्कोहल जैसी चीजें बिल्कुल न दें।

सर्पदंश से कैसे बचें

यदि आप कोई सांप देखें तो उसे न छेड़ें, वो आपसे खुद ही दूरी बना लेगा। झाड़ियों या फसलों में हाथ या पैर डालने से पहले लकड़ी या डंडे से टटोल लें। रात में हमेशा टाच की मदद से घर और बाहर दोनों जगह को अच्छी तरह देख कर काम करें। घर के आसपास साफ-सफाई रखें और चूहों को न रहने दें, सांप चूहों से आकर्षित होते हैं। रास्तों और पगडंडियों को गिरी हुई पत्तियों और घास-फूस से मुक्त रखें। घर के बाहर हमेशा जूते या चप्पल पहन कर काम करें। जमीन में न सोएं और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरगंवा में लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज की उपस्थिति में विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरगंवा तिलक लगा, फूलमाला पहनाकर, मिठाई खिलाकर नवप्रवेशी बच्चों का किया गया स्वागत



अम्बिकापुर। अम्बिकापुर विकासखण्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरगंवा में मंगलवार को विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज उपस्थित रहे। इस अवसर पर विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विद्यालय के शिक्षक तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने मनमोहक नृत्य कर अतिथियों का स्वागत किया। अतिथियों सहित अधिकारियों ने नवप्रवेशी बच्चों को तिलक

लगाकर, फूलमाला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। शाला प्रवेश उत्सव में नवप्रवेशित बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए विधायक श्री प्रबोध मिंज ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और शासन द्वारा शिक्षा स्तर की गुणवत्ता को बेहतर से बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। इस दौरान अतिथियों द्वारा विद्यालय परिसर में बने नवनिर्मित पांच कक्षाओं का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही सरस्वती सार्याकिल योजना के तहत 42 छात्राओं को निःशुल्क सायकल का वितरण किया गया। साथ ही च्यक पेड़ मां के नामच्च् अभियान के तहत स्कूल परिसर में जनप्रतिनिधियों द्वारा पौधारोपण किया गया।

कलेक्टर ने शासकीय प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास डुमरिया के छात्रावास अधीक्षक को किया तत्काल प्रभाव से निर्लंबित

जशपुर नगर। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने फरसाबहार के मण्डल संयोजक द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार शासकीय प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास डुमरिया के छात्रावास अधीक्षक (श्रेणी द) श्री नरसिंह मलार्ज को तत्काल प्रभाव से निर्लंबित किया है। साथ ही निर्लंबन अवधि में श्री मलार्ज, छात्रावास अधीक्षक का मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, जशपुर निर्धारित किया गया है। इन्हें निर्लंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह

भत्ते की पात्रता होगी। मण्डल संयोजक विकासखण्ड फरसाबहार द्वारा 06 जुलाई 2024 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि शासकीय प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, डुमरिया में पदस्थ श्री नरसिंह मलार्ज,अधीक्षक (श्रेणी द) द्वारा दिनांक 06 जुलाई 2024 को शाम को नशे की हालत में छात्रावास में निवासरत् छात्रों के साथ आभद्र व्यवहार तथा मार-पीट की गई। जिसके कारण कलेक्टर डॉ. मित्तल ने छात्रावास अधीक्षक श्री नरसिंह मलार्ज का यह

एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में लगाए जाएंगे पौधे

अम्बिकापुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 12 जुलाई को विभाग द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसके तहत जिले के समस्त 2503 आंगनवाड़ी केंद्रों में 5-5 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा। विभाग द्वारा 15 हजार से अधिक पौधे रॉपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त जल शक्ति से नारी शक्ति अभियान का आयोजन भी कराया जाएगा, जिसमें विभाग द्वारा ग्राम की महिला समूहों, महिला मंडल, ग्राम स्तर की सभी महिलाओं में जल संचयन हेतु जनजागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा तथा जल संरक्षण के सम्बन्ध में शपथ भी दिलाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 08 जुलाई से 12 जुलाई तक प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना अंतर्गत मातृत्व लाभ सप्ताह का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को योजना के सम्बन्ध में जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर आंगनवाड़ी केंद्रों में महतारी वंदन सम्मलेन का भी आयोजन कराया जाएगा, जिसमें योजना से लाभान्वित हितग्राहियों को योजना से प्राप्त राशि को अपने तथा अपने बच्चों के पोषण में खर्च करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन ने की अपील

सूरजपुर। कलेक्टर श्री रोहित व्यास द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि बाल विवाह की रोकथाम में सहयोग प्रदान करें। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का निर्गम उल्लंघन हैं। बाल विवाह से पोषण व शिक्षा पाने और हिंसा, उत्पीड़न व शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है। कम उम्र में विवाह से बालिका का शारीरिक विकास रूक जाता है। उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। जल्दी विवाह अर्थात जल्दी माँ बनना इसके कारण कम उम्र में माँ और उसके बच्चें दोनों की जान और वजन कम रह जाता है और उनके वृषोषित होने की आशंका रहती है। अतः जिले वासी से अपील है

कि बाल विवाह ना करे एवं बाल विवाह ना होने देवे। बाल विवाह की रोकथाम में शासन प्रशासन का सहयोग करे।

17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के दिन से वैवाहिक सीजन शुरू हो जाता है। अबूझ मुहूर्त के कारण अक्षय तृतीया के दिन भी बड़ी संख्या में शादियों होती है। ग्रामीण अंचलों में तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवज अपने बच्चों की कम उम्र में ही शादी कर देने तैयार हो जाते हैं जो कि कानून गलत है। ऐसे बालक-बालिका जो कि नाबालिक हैं उनकी शादी ना हो, उनके लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से सक्रिय है। जिले में बाल विवाह की पूर्णतः रोकथाम हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग पूरे जिले में नजर रखने की तैयारी कर चुका है।

जिले के साथ ग्रामीण अंचल में काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के माध्यम से किसी भी गांव या शहर के कम उम्र के बालक या बालिका की शादी ना हो इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है।

विभागीय अमला पूरी सक्रियता के माध्यम से कार्य कर रहा है। 21 वर्ष से कम आयु के लड़कें और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह कानूनन प्रतिबंधित है। कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है, उसमें सहायता करता है, बाल विवाह को बढ़ावा देता है, उसकी अनुमति देता है अथवा बाल विवाह में सम्मिलित होता है, को 02 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि एवं सामाजिक विकास के लिए समन्वय के साथ करें कार्य – जनक ध्रुव

गरियाबंद। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत देश के 500 ब्लॉकों में संपूर्णता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत जिले के 2 विकासखंड गरियाबंद और मैनपुर का चयन हुआ है। इसी तारतम्य में बिन्दानवागढ़ विधायक श्री जनक ध्रुव ने आम मैनुष ब्लॉक में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया। सामुदायिक भवन मैनपुर में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, एएनएम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं भारी संख्या में आमजन शामिल हुए। संपूर्णता अभियान के शुभारंभ अवसर पर विधायक श्री ध्रुव ने कहा कि नीति आयोग द्वारा पिछड़े ब्लॉकों के विकास के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी के तहत आकांक्षी ब्लॉक में लोगों के सम्पूर्ण विकास के लिए संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 6 इंडिकेटर निर्धारित किए गए हैं। जिसे 30 सितंबर तक पूर्ण करने का कार्य योजना बनाया गया है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में लोगों को शत प्रतिशत लाभान्वित करना है। उन्होंने नीति आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को लोगों के विकास एवं संवर्धन के लिए मिलजुल कर समन्वय के साथ काम करने की अपील लोगों से की। विधायक श्री ध्रुव ने मैनपुर क्षेत्र के विकास के लिए महिलाओं को भी आगे आकर अभियान में शामिल होने कहा। उन्होंने संपूर्णता अभियान के तहत प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, शूगर बीपी जांच, पूरक पोषण आहार वितरण, स्व सहायता समूह को आवश्यक सहायता एवं किसानों को मुद्रा परीक्षण स्वाइल कार्ड वितरण के लिए जागरूक होकर अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में विधायक एवं कलेक्टर ने स्टाल का अवलोकन कर बीपी और मधुमेह स्तर की भी जांच कराई। साथ ही महिला बाल विकास विभाग द्वारा पोषण आहार से संबंधित स्टाल का भी अवलोकन कर अधिक से अधिक महिलाओं एवं बच्चों को पोषण आहार से

प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा हमारा मौलिक कर्तव्य – कलेक्टर व्यास

सूरजपुर। जिला मुख्यालय में स्थित शिव पार्क में एक 'पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर श्री रोहित व्यास एवं पुलिस अधीक्षक श्री एम आर अहिर द्वारा पौधा रोपण किया गया।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री व्यास ने बताया कि वृक्षारोपण एवं प्राकृतिक पर्यावरण (वन, वन्यजीव, झील, नदी इत्यादि) की रक्षा को संविधान में देश की जनता के मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी को पौधारोपण एवं पर्यावरण की रक्षा करने के हरसंभव उपाय करने चाहिए। पृथ्वी के पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए वृक्षों का होना आवश्यक है। इसके लिए सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ पर्यावरण एवं जलवायु को बेहतर करने के उद्देश्य से किया गया है। अतः सभी जिलेवासी इस अभियान में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि सभी अपनी माता के साथ या माता के नाम पर या माता को श्रद्धांजलि देते हुए कम से कम एक पेड़ तो

अवश्य लगाएं। साथ ही इस पेड़ को अपने मातुलुय सम्मान देते हुए उसकी देखभाल करें। उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि पेड़ों को लगाने में ऐसी जगह का चयन करें जहां आप उसकी देखभाल बेहतर तरीके से कर सकें। कलेक्टर ने कहा कि बीते ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत ज्यादा रहा यह भी हमारे पर्यावरण में हो रहे असंतुलन की ओर इशारा करता है। कभी ज्यादा बारिश होना तो कभी बिलकुल बारिश न होना, इसी प्रकार शीत ऋतु में काफी बदलाव दिखाई देना यह सभी पर्यावरण असंतुलन की ओर इंगित करता है। उन्होंने वृक्षारोपण करने वाले सभी शासकीय विभागों को कहा कि वृक्षारोपण अभियान की सफलता के लिए वृक्षारोपण पश्चात उसकी नियमित रूप से ऑर्डिटिंग आवश्यक है। वृक्षारोपण के पश्चात सही तरीके से देखभाल एवं ऑर्डिटिंग से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है।

इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री अहिरे ने कहा कि वृक्षारोपण करना स्वस्थ पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक है। इससे न केवल पर्यावरण की वायु शुद्ध होती है बल्कि वन्य जीव जंतुओं को आवास भी मिलता है।

महतारी वंदन योजना से बेहतर भविष्य की बंधने लगी आस

धमतरी। महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बीते मार्च माह से महतारी वंदन योजना संचालित की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना से महिलाएं लाभान्वित होकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहीं हैं। योजनांतर्गत प्रतिमाह एक हजार रुपये महिलाओं के बैंक खाते में सीधे अंतरित होने से प्रदेश की महिलाओं के मन में बेहतर भविष्य की आस बंधने लगी है।

योजना से लाभान्वित हुई सहेली संघ स्व सहायता समूह धमतरी की सदस्य श्रीमती हेमा साहू ने बताया कि उनके साथ श्रीमती ललिता साहू, श्रीमती राशि साहू, श्रीमती संतोषी साहू, श्रीमती रमा सेन, श्रीमती सविता, श्रीमती अनिता यादव सहित उनकी समूह की अन्य महिलाएं कलेक्टरों के



वर्ग के परिवार की महिलाओं के लिए यह योजना आर्थिक मजबूती का आधार बन गयी है। वे इस योजना से मिलने वाली राशि के उपयोग से आर्थिक रूप से सशक्त रह रही हैं। योजना से महिलाएं निजी जरूरतों, परेल् आवश्यकताओं व दैनिक उपयोग की चीजों की खरीदी एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हुई हैं।

पी.एम.श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सुपगाँव में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन

नारायणपुर। विश्व जनसंख्या दिवस एवं राज्य सरकार के पर्यावरण संरक्षण से प्रेरित एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम को पी.एम.श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सुपगाँव नारायणपुर में 11 जुलाई को अति उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय के प्राचार्य एस. के. मण्डल कार्यक्रम के संयोजक वरीष्ठतम शिक्षक श्री अनुपम शुक्ल एवं अन्य शिक्षकों कलामुद्दीन अंसारी, आकाश, अर्पणा, निखिल, प्रशांत,हर्ष, गौरव कार्यालय अधीक्षक श्री सलीम आदि के साथ विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की। इस अवसर पर प्राचार्य श्री मण्डल ने विश्व में बढ़ती जनसंख्या पर अपनी चिंता व्यक्त की और वरीष्ठतम शिक्षक श्री शुक्ल ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागृति और जन सहयोग की भावना को बढ़ाने पर अपने विचार व्यक्त किये। हिन्दी शिक्षक श्री आकाश पटेल ने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इस कार्यक्रम के दूरगामी प्रभाव को लेकर आश्चस्ति व्यक्त की। समाज विज्ञान अध्यापक श्री अंसारी को ने धार्मिक परम्पराओं में पर्यावरण संरक्षण के सूत्रों को व्याख्यायित किया।

32 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल



रायपुर। अपनी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी संघ ने आज से नया रायपुर तृता स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश भर के पटवारी अपने अपने जिलों में हड़ताल कर रहे हैं। पटवारी संघ ने राजस्व मंत्री को अपील को ठुकरा दिया है। पटवारी संघ ने भुइया

हड़ताल से राजस्व पखवाड़े प्रभावित

सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कत-परेशानी, स्कैनर सुविधा, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, इंटरनेट की सुविधा, अतिरिक्त भत्ता सहित 32 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोला दिया है। बता दें कि पटवारियों की

हड़ताल के कारण 6 जुलाई से शुरू हुआ राजस्व पखवाड़े प्रभावित होने की होगा। ऑनलाइन भुइयां साफ्टवेयर में आ रही समस्याओं को लेकर पटवारी संघ ने राजस्व मंत्री को लिखा पत्र, मांग पूरी नहीं होने 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी थी।

बलौदाबाजार हिंसा मामले ने कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव को पुलिस ने जारी किया नोटिस

प्रदर्शन में हुए थे शामिल

बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव को नोटिस जारी किया है। उन्हें 9 जुलाई को पृच्छाछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि देवेन्द्र यादव हिंसा के दिन समाज के प्रदर्शन में कुछ देर के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने बलौदाबाजार में हुई हिंसक झड़प और आगजनी मामले में हाल ही में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे को गिरफ्तार किया था। अब तक इस मामले में 156 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है।



जानिए पूरा मामला

बता दें, 15 और 16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने

गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों

को गिरफ्तार किया था। पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे। इस बीच गृहमंत्री विजय शर्मा ने

न्यायिक जांच की घोषणा की। वहीं 10 जून को जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया। जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसके बाद उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया।

समाज के इस प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव भी शामिल हुए थे। इस मामले में अब तक 156 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है।

सेंट्रल जेल के अफसरों की बड़ी लापरवाही

उम्रकैद की सजा काट रहे बंदी को कर दिया रिहा

बिजली कटौती और बढ़े हुए बिल को लेकर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन

पूर्व सीएम बोले- बिजली बिल देखकर लोगों को लगा 440 वोल्ट का झटका

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस आक्रमक नजर आ रही है। राज्य में जन समस्याओं को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नक्सल समस्या, हसदेव में जंगल की कटाई, राजधानी में सड़क चौड़ीकरण जैसे मुद्दों के बाद अब कांग्रेस बिजली बिल में बढ़ोतरी और लगातार कटौती को लेकर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। आज राजधानी रायपुर समेत राज्य के कई जिलों में कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं ने बिजली की समस्या को लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया।

राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत,



महापौर दीपक बैज समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए। इसके बाद सभी हाथों में लालटेन लेकर पैदल मार्च करते हुए बूढ़ापारा बिजली ऑफिस पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। बिजली की कटौती एवं बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। विष्णु देव साय से ऊपर वाला भी रूठ गया, पानी तक नहीं गिर रहा। हमारी सरकार में कभी अकाल की स्थिति नहीं हुई, लेकिन विष्णुदेव सरकार से भगवान भी नाराज हैं, पानी तक

नहीं गिर रहा है। जिस राज्य में कोयला उत्पादन, वहां बिजली कटौती हो रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली बिल देखकर लोगों को 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। अधोषिप्त बिजली कटौती और दरों में बढ़ोतरी से जनता परेशान है।

बता दें कि पूर्व सीएम बघेल अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि साय सरकार में सांघ-सांघ बिजली कटौती हो रही है।

रायपुर। सेंट्रल जेल रायपुर में जिम्मेदार अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार के इंकार के बाद भी उम्र कैद की सजा काट रहे एक बंदी को रिहा कर दिया गया। इसकी जानकारी होते ही जेल में हड़कंप मचने पर आठ दिन बाद फिर उसे पकड़कर जेल में डाला गया।

रायपुर सेंट्रल जेल के जेलर अमित शांडिल्य ने बताया कि उम्रकैद के कैदी को त्रुटिपूर्वक रिहा कर दिया गया था। इसकी सूचना मिलते ही जेल प्रशासन ने तत्काल कैदी को जेल दाखिला करावा दिया है। इस घटना क्रम की जांच की जा रही है। दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।



जानिए क्या है पूरा मामला

बलौदाबाजार जिले के मड़वा गांव निवासी महावीर पिता छतराम को हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा हुई थी। सजा की 14 साल की अवधि पूरी होने के बाद अच्छे आचरण के लिए छह साल की सजा माफी

का प्रस्ताव रायपुर जेल ने सरकार को भेजा था, मगर सरकार ने सजा कम करने से इंकार कर दिया था। इसके बाद भी जेल अधिकारियों ने 4 जून को महावीर को रिहा कर दिया। कैदियों के बीच ये बात फैलने लगी कि बंदी को बिना सरकार की अनुमति सजा माफी देते हुए

रिहा कर दिया गया है

इस पर जेल के अधिकारियों को लगा कि बात कहीं उपर तक पहुंच जाएगी तो वे नप जाएंगे। इसके चलते जेल के कुछ कर्मचारियों को महावीर के गांव मड़वा भेजा। उनके साथ आसपास के पूर्व में रिहा हुए कुछ बंदी भी थे। महावीर घर में मिल गया। उसे बताया गया कि जेल में एकाध कागजी औपचारिकता रह गई है, उसे पूरा कराकर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। जेल पहुंचने के बाद महावीर को फिर बैरक में डाल दिया गया।

जमीन विवार पर एक व्यक्ति की

हुई थी हत्या

हत्या की घटना 1998 की है। गिरौधपुरी के मड़वा गांव में पारिवारिक जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। महावीर समेत कई लोग उसमें आरोपी बनाए गए थे। इस केस में महावीर को उम्र कैद की सजा हुई। पिछले 14 सालों से वह जेल में है। जानकारों का कहना है कि अच्छे आचरण के आधार पर छह महीने की सजा माफी हो जाती है। इसके लिए जिस कोर्ट से सजा हुई हो, अभिमत के लिए पेपर भेजा जाता है। इस मामले में बलौदाबाजार कोर्ट ने रिहा करने का अभिमत दे दिया था। इसके बाद सेंट्रल जेल से सरकार को पत्र भेजा गया। सरकार ने इसे अमान्य कर दिया।

बच्चों का नया स्कूल तैयार, जर्जर प्राथमिक शाला से मिली आजादी



मुख्यमंत्री जतन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 - 23 में 12 लाख 80 हजार रूपए स्वीकृत किया गया। निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के लिए मोहल्ले के भीतर प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कराना मुश्किल का काम था। मोहल्ले में कई नागरिक स्कूल के काम में सहयोग देते हैं तो कई अवरोध उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में ठेकेदार के लिए भवन निर्माण करना बहुत दुष्कर था। ठेकेदार प्रति दिन के हिसाब से निर्माण सामग्री रेत, गिट्टी, सीमेंट, छड़ आदि का उपयोग कर बनाया है।

सारंगढ़। जिला मुख्यालय और नगर पालिका परिषद सारंगढ़ के घसियापारा में प्राथमिक शाला भवन जर्जर था, जिसका नया भवन लगभग 10 वर्ष बाद निर्मित हुआ है। प्राथमिक शाला भवन जर्जर होने के कारण अतिरिक्त कक्ष में प्राथमिक शाला का संचालन किया गया। अतिरिक्त कक्ष का भी भवन जर्जर होने पर वर्ष 2018 में सामुदायिक भवन में प्राथमिक शाला का संचालन किया गया। इस प्रकार राज्य शासन की ओर से

प्राथमिक शाला घसियापारा सारंगढ़ की प्रधान पाठक राधिका सिदार कहती हैं कि प्राथमिक शाला भवन के नया बनने से बच्चे बहुत खुश हैं। साथ ही पुराने भवन के जर्जर स्थिति से अब आजादी मिली है। पालक भी जर्जर भवन के कारण स्कूल भेजने में हिचकिचाहट व्यक्त करते थे, लेकिन नया स्कूल भवन बनने से बच्चों और पालकों में भी उत्साह और खुशी है।

कोसा की पहचान देश विदेश में मिलकर करेंगे बेहतर कार्य- आकाश छिकारा



जांजगीर। जिलाधीश आकाश छिकारा ने ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत हस्तशिल्प, रेशम, खादी, हथकरघा, उद्योग विभाग के विभिन्न घटकों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति के संबंध में ली जानकारी। उन्होंने सभी अधिकारियों को विभाग में संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने एवं लाभान्वित हितग्राहियों के आय में वृद्धि करने के लिए व्यक्तिगत संच लेकर कार्य करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही उनके उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर उन्हें विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए कहा।

जिले जांजगीर चाम्पा की पहचान कोसा

हितग्राहियों को आवश्यक सुविधाएं उपकरण एवं प्रशिक्षण भी दिलाने की बात श्री छिकारा ने कहा। उन्होंने कहा कि जिले जांजगीर चाम्पा की पहचान कोसा है और इसकी बेहतरी के लिए प्रशासन के साथ ही कोसा से जुड़े बुनकर, हथकरघा उद्योग से जुड़े व्यवसायी

समन्वय बना कर कार्य करेंगे। उन्होंने इस दौरान विभागीय योजनाओं से लाभान्वित हुए हितग्राहियों से उनके कार्यों एवं उनकी समस्याओं के सम्बंध में किया चर्चा। इस दौरान र ट क होल्डर, बुनकर, धागाकरण, कृमिपालन हितग्राहियों से चर्चा करते हुए लिया सुझाव।

हितग्राही विभागीय योजनाओं

का उठाए लाभ

उन्होंने कहा कि हितग्राही विभागीय योजनाओं का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जिले में कोकूर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रेशम विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के विभिन्न कक्षा का किया निरीक्षण। उन्होंने संस्थान के द्वारा दिए जा रहे पाठ्यक्रम की लिया जानकारी। उन्होंने जकाई प्रयोग शाला कक्ष, पावरलूम, हेफडलूम के तहत संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर दुर्गा प्रसाद अधिकारी, एसडीएम चांपा नीरनिधि नंदेहा, सहायक संचालक हाथकरघा, सहायक संचालक रेशम विभाग, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी व्यवसायी एवं हितग्राही गण उपस्थित रहें।

लंबे समय से गायब 66 डॉक्टरों को नोटिस जारी, बर्खास्त करने की तैयारी

गैरजिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार सख्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने गैरजिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य विभाग ने कई दिनों से ड्यूटी से गायब रहने वाले राज्य के 66 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सभी डॉक्टरों से उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की बात कही गई है। मामले में अनुपस्थित डॉक्टरों की विभागीय जांच होने और आरोप सही पाए जाने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कार्यालय प्रमुख से प्राप्त जानकारी अनुसार आप अपने पदस्थापना स्थल से दिनांक के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध छग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2014/1-3 10.02.2015 में उल्लेख है कि एक माह या उससे अधिक समय तक

अनाधिकृत अनुपस्थित को सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 27 सहपठित मूलभूत नियम 17-ए के अधिन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा से व्यवधान माना जावे। ऐसे शासकीय सेवकों का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किये जावे। साथ ही ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल दीर्घशक्ति के लिये विभागीय जांच संस्थित की जावे। इसका निराकरण अधिकतम 6 माह की समायावधि में कर लिया जावे।

आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने की शक्ति दी जावे। पत्र जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें अनुपस्थिति अवधि के संबंध में कार्यालय प्रमुख के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

छिंदई नदी में बना उच्च स्तरीय पुल, ग्रामीणों के लिए आवागमन का रास्ता गया खुला

कोरबा। बारिश के साथ ही उफान पर रहने वाले मदवानी के इस छिंदई नदी को पार कर पाना आसपास के ग्रामीणों के लिए कितना जोखिम भरा होता था, यह तो ग्रामीण ही जानते हैं। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना हो या फिर अपने किसी परिचित के घर जाना हो, लंबे समय तक

पुल नहीं होने का खामियाजा भुगतना पड़ता था। बारिश आते ही महीनों तक बहुत से लोगों की या तो भेंट मुलाकात बंद हो जाती थी, या फिर लंबी दूरी तय कर एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। इस लंबी दूरी को तय करने के लिए उन्हें अतिरिक्त पैसे तो खर्च करने ही पड़ते थे, इसके

साथ ही बहुत ज्यादा समय भी देना पड़ता था। अब जबकि इस छिंदई नदी में पुल बन गया है, ग्रामीणों का आवागमन आसान बन गया है। वे आसानी से घंटों की दूरी मिनटों में तय कर पहुंच जाते हैं।

कतरला विकासखंड के ग्राम मदवानी -कछार-तराईमार -

कुदमुरा मार्ग में छिंदई नदी में लगभग 17 करोड़ 17 लाख की राशि से बने उच्च स्तरीय पुल का हाल ही में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरूण साव ने लोकार्पण किया था। रामपुर, मोकामाई सहित आसपास के अनेक गांव को कुदमुरा, हाटी

सहित प्रमुख मार्गों से जोड़ने में यह पुल ग्रामीणों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। इस पुल के बन जाने से विकास के नए द्वार खुल गए हैं। वर्षों से इस नदी में पुल की मांग थी जो अब पूरी हो गई है। इससे आसपास के अनेक गांव जुड़ गए हैं। एक दूसरे से सम्पर्क भी बढ़ गया है।

यह पुल आवागमन का पुल होने के साथ ही विकास का भी पुल बन गया है। इस पुल को पार करते हुए ग्रामीण कमल सिंह चौहान ने बताया कि पहले उन्हें लंबी दूरी तय करके एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। उन्हें पार करने से 10 किलोमीटर अतिरिक्त वाहन बाइक घुमाना

पड़ता था। इससे उनके अतिरिक्त रूपये और समय का नुकसान होता था। उन्होंने बताया कि गर्मी के दिनों में नदी में पानी कास्तर कम होने पर बहुत से ग्रामीण जोखिम उठाकर नदी पार कर लेते थे। बारिश में नदी का स्तर बढ़ने पर पुल पार करना खतरनाक बन जाता था। अब

जबकि पुल बन गया है। आवागमन में आसानी होने के साथ ग्रामीणों को बहुत सहूलियत होने लगी है। ग्राम मदवानी के किसान श्री भुनेश्वर राठिया का कहना है कि गांव में रहने वाले लोगों का दूसरे गांव तक रिश्तेदारों के पास सुख-दुख में आना-जाना रहता है।

न्यूज रूटीन

● बलौदाबाजार
● जुलाई 2024

07

24 जुलाई तक मनाया जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस एवं जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा



महिला नसबंदी के प्रति फैली अज्ञानता व भ्रांतियों को दूर कर परिवार नियोजन के महत्व के बारे में जनता को जागरूक किया जा रहा, इस पखवाड़े में लक्ष्य दंपतियों को उसकी पसंद के अनुसार परिवार नियोजन के अस्थाई साधन, जिला चिकित्सालय तथा विकास खण्डों में पुरुष एवं महिला नसबंदी शिविर का आयोजन शामिल है। शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में परिवार नियोजन के साधन निशुल्क उपलब्ध हैं। इसमें पुरुष एवं महिला नसबंदी, निरोध, गर्भनिरोधक गोली, अंतर इंजेक्शन, कॉपर टी जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

नसबंदी उपरांत हितग्राहियों को महिला नसबंदी हेतु 2000 तथा पुरुष नसबंदी हेतु 3000 प्रोत्साहन राशि शासन द्वारा दिया जायगा। कोरबा जिलाधीश अजीत वसंत तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के परिवार नियोजन के पात्र इच्छुक दंपतियों से अपील जाहिर किया है, कि अपने परिवार को सीमित रखने हेतु अधिक से अधिक संख्या में परिवार नियोजन के अस्थाई तथा स्थाई साधन का उपयोग करें। जिससे उनका परिवार सुखी और खुशहाल हो सके।

कोरबा। जिले में परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु 24 जुलाई 2024 तक विश्व जनसंख्या दिवस एवं जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। जिलाधीश वसंत के निर्देश पर जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा प्रचार-प्रसार रथ को रवाना किया गया। यह रथ जिले के सभी विकास खण्डों में घूम कर परिवार नियोजन के स्थाई तथा अस्थाई साधन के संबंध में जागरूकता प्रदान करेगा। सी.एम.एच.ओ. ने बताया कि जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा के दौरान ग्राम स्तर से जिला स्तर तक विशेष अभियान चलाकर पुरुष एवं

बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल की फरार महिला आरोपी गिरफ्तार

वकील से मिलने पहुंची तो पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा, अब तक 5 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

अरविन्द मिश्रा (सुघर गांव)। बलौदाबाजार के बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में पुलिस को चकमा देकर तीन महीने से फरार चल रही महिला पुष्पमाला फेकर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आज महिला अपने वकील से मिलने पहुंची थी जिसकी सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले ही पुलिस चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्हें अदालत से जमानत मिल चुकी है। वहीं इसमें अभी भी तीन आरोपी



शिरौष पांडे, आशीष शुक्ला और हीरा कली बंजारे फरार हैं। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बलौदाबाजार में लंबे समय से चल रहे सेक्स स्कैंडल कांड में कई सफेदपोश लोगों के नाम सामने आए थे। इसमें कई जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मी, वकील, कथित पत्रकार व अन्य

की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। साथ ही यह भी खबर सामने आई थी कि कई लोगों को बूटे सेक्स केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे लाखों रुपये वसूल गए थे। इस अवैध वसूली को लेकर भी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों के घर की

तलाशी लेने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले में तीन अन्य आरोपियों दुर्गा टंडन, मोंटी उर्फ प्रत्युष मारईया और रवीना टंडन को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सेक्स स्कैंडल कांड के मुख्य आरोपी शिरौष पांडे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई। जिसमें कोर्ट ने शिरौष पांडे के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

सेक्स स्कैंडल के आरोपियों पर एसपी ने घोषित किया है इनाम

सेक्स स्कैंडल मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशों के बाद भी पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही थी। जिसके बाद तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार ने 7 जून 2024 को 4 आरोपियों को पकड़ने में मदद करने वाले को पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की थी। जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार यानी 9 जुलाई को चार आरोपियों में से एक महिला आरोपी पुष्पमाला फेकर को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है।

सोशल मीडिया में हुई दोस्ती, युवती की आवाज निकाल शादी का दिया झांसा, फिर ऐंठे करोड़ों रुपए

बिलासपुर। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भारी पड़ गया। इमोशनल ड्रामा कर युवक ने लड़की बनकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी कर ली। दोस्ती के बाद आरोपी युवक ने युवती की आवाज निकालकर इंजीनियर को शादी का झांसा दिया और अलग-अलग किश्तों में पैसे ट्रांसफर करा लिए, ठगी का एहसास होने पर युवक ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।



मिली जानकारी के अनुसार, सरकंडा में रहने वाला नितिन जैन (40) पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नितिन जैन ने पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले सोशल मीडिया में एक युवती से उसकी

दोस्ती हुई थी, जो लड़का निकला। उसने खुद को पुणे में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया था। दोस्ती के बाद उन्होंने अपने-अपने नंबर शेयर किए थे।

पैसे की डिमांड बढ़ने पर हुआ ठगी का एहसास

एसपी रजनेश सिंह ने बताया, प्रार्थी के मुताबिक, युवती ने पहले उसे प्रेम के झांसे में लिया, फिर इमोशनल ड्रामा करते हुए पारिवारिक परेशानी बताकर कुछ पैसे की जरूरत बताई। युवती ने नितिन जैन के सामने

शादी का प्रस्ताव भी रख दिया। वह मान भी गया। इसके बाद नितिन युवती को धीरे-धीरे लगभग 1 करोड़ 39 लाख रुपये दे दिए। लगातार पैसे की डिमांड बढ़ने के बाद भी जब युवती ने मिलने और शादी की बात से मना किया तो नितिन को संदेह हुआ। इस बार नितिन ने मिलकर पैसे देने की बात कही तो युवती फिर से बहाना बनाने लगी। जब नितिन को ठगी का एहसास हुआ तो उसने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर मामला दर्ज कर आरोपी रोहित जैन पिता रमेश चन्द्र कररा बाजार में रह रहे हैं। को गिरफ्तार कर लिया गया है।



बलौदाबाजार घटना को लेकर डीजीपी से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेसियों की गिरफ्तारी पर की चर्चा

रायपुर। बलौदाबाजार घटना और प्रदेश की विगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज डीजीपी से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने एनएसयूआई और युथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर चर्चा की।

डीजीपी से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक धनंजय साहू, सत्यनारायण शर्मा, फूलोदेवी नेताम, सुबोध हरितवाल, राजेंद्र तिवारी, देवेंद्र यादव शामिल थे।

प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार नैतिकता, संस्कार और अध्यात्म से विकसित होंगे सकारात्मक विचार-सांसद नाग

कांकेर। जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन आज अंतागढ़ के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री भोजराज नाग उपस्थित थे। इस दौरान नौनिहाल बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाकर उन्हें

निःशुल्क पुस्तक, गणवेश और साइकल वितरित की गई। साथ ही जिले के विभिन्न स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं में शत प्रतिशत परिणाम लाने के लिए सांसद एवं कलेक्टर के द्वारा संस्था के प्राचार्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि को आसंदी से सांसद श्री नाग ने कहा

कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है और केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का समुचित लाभ ले सकता है। नैतिकता, संस्कार और

अध्यात्म से विकसित होंगे सकारात्मक विचार = सांसद श्री नाग विकासखंड मुख्यालय अंतागढ़ के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने आगे कहा कि गुरु-शिष्य परंपरा भारत की

प्राचीन और उत्कृष्ट शिक्षा पद्धति रही है, जिसे फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नैतिकता, संस्कार, मानवता और अध्यात्म से ही सकारात्मक सोच विकसित हो सकती है। सांसद ने सभी विद्यार्थियों को शाला प्रवेशोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए उनके

उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर कलेक्टर श्री नीलेश महादेव क्षीरसागर ने जिला प्रशासन की ओर से संदेश का वाचन करते हुए कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए जिले में अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी बाहुल्य

कांकेर जिले में 05 एकलव्य आवासीय विद्यालय और एक प्रयास विद्यालय सहित अनेक स्कूल, आश्रम, छात्रावास हैं जिनके जरिए विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता हेतु तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा प्रतियोगी व व्यावसायिक प्रतीक्षाओं के लिए

भी उन्हें सतत मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसके पहले नगर पंचायत अध्यक्ष श्री राधेताल नाग ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में सांसद श्री नाग व अन्य मंचस्थ अतिथियों के द्वारा 06 दिव्यांग छात्राओं को चश्मा, ब्रेल किट और दिव्यांगत प्रमाण पत्र दिया गया।

बलौदाबाजार के होटल और दुकानों पर खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 8 को जारी की नोटिस



किलोग्राम चिकन फ्राई में डस्ट पार्टिकल पाया गया। इसी तरह जायका रेस्टोरेंट के वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों का उचित

पदार्थों को तुरंत नष्ट कराया गया। इसी तरह किशन फल भण्डार, जयफल भंडार में भी फलों की जांच की गई। इस दौरान फलों को नियमानुसार पकाया जाने की हिदायत दी गई। दुकानदारों के अधिकारियों ने दिए ये निर्देश खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश वर्मा ने बताया, निरीक्षण के दौरान सभी को खाद्य पदार्थों के सही रख-रखाव पीने के पानी का साफ बर्तन में भण्डारण करने, खाद्य पदार्थ को मक्खी से बचाव हेतु ढक कर रखने, अखबार पेपर का उपयोग नहीं करने, तेल में 03 बार से अधिक नहीं तलने, एकपाइयरी डेट वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करने एवं साफ-सफाई रखने की निर्देश दिए गए हैं।

रूको प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है

ग्राम पंचायत मुड़ापार में किया गया बोर खनन, निकला भरपूर पानी का धार

हरदी बाज़ार। जिले कोरबा के जनपद पंचायत पाली अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुड़ापार पोस्ट कोरबी थाना व तहसील हरदी बाज़ार में बोर खनन किया गया। जिसमें गांव वालों ने खुशी जाहिर की। गांव वाले पानी की जटिल समस्या से जूझ रहे थे बोर खनन होने से ग्रामीणों ने भरपूर पानी निकलने को लेकर खुशियों का बहार टूट पड़ा। आपको बता दें कि ये बोर खनन गांव में क्षेत्र के जनपद पंचायत सदस्य भवानी राजेश राठौर के द्वारा 15 वें वित्त योजना जनपद स्तर मद से कराया गया जिसका स्वीकृत राशि 200000/- (दो लाख) रूपए है।



जिसकी स्वीकृति 18.05.2023 को प्रदाय किया गया था। बोर खनन सब मार्शीबल पम्प पानी टंकी निर्माण कार्य ग्राम पंचायत मुड़ापार (धौराभाठा) में जो अब जा कर पूर्ण हुआ। जिससे मोहल्ले वासियों में खुशी का माहौल है।

ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग, 1.25 करोड़ का सामान जलकर खाक



कोरबा। पावर सिटी कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आकांक्षा इंटरप्राइजेज नामक ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची लेकिन आग तेजी से फैल गई और दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। काफी मशकत के बाद दमकल

विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। इस आगजनी की घटना में करीब सवा करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, टीपी नगर स्थित प्लॉट नंबर 185 में ऑटो पार्ट्स की दुकान में दोपहर करीब 12 बजे आग लग गई। दुकान संचालक सत्येंद्र केसरवानी

ने बताया कि उसकी दुकान आकांक्षा इंटरप्राइजेज के नाम से संचालित है। सुबह लगभग 9 बजे दुकान खोल पूजा पाठ करने के बाद वह 12 बजे बच्चों को स्कूल लेने जाने के नाम से दुकान बंद कर निकला हुआ था। उसे फोन पर जानकारी मिली कि उसकी दुकान में आग लग गई है और तत्काल वह मौके पर पहुंचा।

जहां उसने देखा की दुकान के अंदर से धुंआ निकल रहा था। जिसके बाद उसने किसी तरह दुकान का शटर तोड़ा और अंदर देखा तो आधा सामान जल चुका था। आग की लपटें भी तेज हो गई थीं। वहीं देखते ही देखते दुकान के बाहर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसकी सूचना पर तत्काल 112 और सीएसईबी चौकी पुलिस को दी गई। वहीं नगर सेना की दमकल वाहन को भी मौके पर बुलाया गया। इस दौरान काफी मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया।

गरीबी रेखा कार्ड बनाने के लिए पैसे लेने वाला अधिकारी निलंबित

कोंडागांव। गरीबी रेखा कार्ड बनाने के लिए गरीबों से पैसे लेने वाले नगरपालिका अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा नगरपालिका अधिकारी के खिलाफ लगातार शिकायत आ रही थी। विधायक लता उसेंडी भी उनके काम से नाखुश थीं। अफसर के काम से क्षेत्र की जनता भी नाराज थीं।

दरअसल कोंडागांव नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र पात्रे के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी कि वह गरीबी रेखा



अफसर के काम से नाखुश विधायक लता उसेंडी ने लगाई थी फटकार

कार्ड के लिए गरीबों से 500-500 रुपए की राशि नियम विरुद्ध

ले रहे हैं। कलेक्टर ने इसकी गोपनीय तरीके से जांच कमेटी से

इसके अलावा कोंडागांव विधायक लता उसेंडी भी उनके

जांच करवाई थी। शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर ने कार्रवाई के लिए राज्य शासन को लिखा था। इस पर राज्य शासन ने एक्शन लेते हुए नगर पालिका अधिकारी का निलंबन आदेश जारी किया।

कार्य से असंतुष्ट थी। हाल ही में उनके कार्य को लेकर विधायक ने फटकार लगाई थी और उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही थी। नगर पालिका अधिकारी के कार्य से आम लोग भी खुश नहीं थे। क्योंकि वह जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बगैर ही कार्य कर रहे थे। 2 दिन पूर्व ही नगर पालिका अधिकारी जैसीबी लेकर बस स्टैंड की दुकानों में तोड़फोड़ करने पहुंच गए थे, जिसको लेकर विधायक लता उसेंडी भी मौके पर पहुंचकर इन्हें फटकार लगाई थी।